राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय
दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
संपर्क नं.-7490923915
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण गुरुवार 10 सितंबर 2026 वर्ष-9,अंक-219 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

पहला कॉलम

पीएम मोदी के जनसेवा के 25 साल पूरे होने पर बीजेपी का 'सेवा संकल्प अभियान,10 दिन निकलेगी यात्रा

बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन बोले- 25 साल की सेवा यात्रा को जन-जन तक पहुंचाएंगे

17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक देशभर में होंगे कार्यक्रम

नई दिल्ली ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। इसी क्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने 'सेवा संकल्प अभियान' की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन में जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और उन्होंने अपना जीवन राष्ट्रसेवा के लिए समर्पित किया है। दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में नितिन नवीन ने बताया कि अगले 10 दिनों में पार्टी की ओर से 'सेवा यात्रा' निकाली जाएगी, जो बनारस से वडनगर तक जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री 7 अक्टूबर 2026 को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करेंगे। इसी उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए पूरे देश में विभिन्न सेवा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

7 अक्टूबर 2001 से शुरू हुई सेवा यात्रा भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की जनसेवा की यात्रा 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभालने के साथ शुरू हुई थी। उनके मुताबिक, पिछले 25 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से राष्ट्रसेवा तक की यात्रा को निरंतर आगे बढ़ाया है। नितिन नवीन ने कहा कि भाजपा का उद्देश्य प्रधानमंत्री के सेवा और समर्पण के संदेश को देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाना है। इसके लिए 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सरकार की उपलब्धियां गिनाईं भाजपा अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के कार्यकाल में देश में कई बड़े फैसले लिए गए और आम लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास हुए।

उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार के दौरान करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष देश की सेवा, विकास और जनकल्याण के लिए समर्पित रहे हैं।

गृहमंत्री अमित शाह 13-14 सितंबर को मुंबई दौरे पर, एशियाटिक सोसायटी और राजभाषा सम्मेलन में होंगे शामिल

मुंबई।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 13 और 14 सितंबर को दो दिवसीय मुंबई दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे फोर्ट स्थित द एशियाटिक सोसायटी का दौरा करेंगे और नवी मुंबई के वाशी स्थित सिडको प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शामिल होंगे। शाह के दौरे को लेकर प्रशासन और संबंधित संस्थाओं की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। शाह अपने दौरे के पहले चरण में एशियाटिक सोसायटी पहुंचेंगे। प्राच्यविद्या और शोध के समृद्ध इतिहास से जुड़ी इस संस्था में वे पदाधिकारियों और सदस्यों से संवाद करेंगे। इस दौरान उनके लिए दुर्लभ पोथियों और ऐतिहासिक संदर्भ सामग्री की प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। प्रदर्शनी में पांच खंडों में प्रकाशित पांडुरंग वामन काणे के प्रसिद्ध ग्रंथ 'धर्मशास्त्र का इतिहास' से संबंधित सोसायटी में संरक्षित संदर्भ सामग्री भी प्रदर्शित की जाएगी। आपको बता दें कि एशियाटिक सोसायटी को 'राष्ट्रीय महत्व की संस्था' का दर्जा देने की मांग पिछले चार वर्षों से केंद्र सरकार के समक्ष लंबित है। अमित शाह के दौरे को देखते हुए इस मांग के पूरा होने की उम्मीद फिर से बढ़ी है। संभावना है कि सोसायटी के पदाधिकारी मुलाकात के दौरान यह मुद्दा केंद्रीय गृहमंत्री के सामने रखेंगे। सोसायटी की हालिया चुनावी गतिविधियां भी चर्चा में रही थीं। जुलाई में हुए चुनाव में 'एशियाटिक टुमारो' समूह ने जीत दर्ज की थी और भाजपा के पूर्व सांसद डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे को अध्यक्ष चुना गया था। बताया जा रहा है कि उनके निमंत्रण के बाद अमित शाह का सोसायटी दौरा तय हुआ है। वाशी में राजभाषा सम्मेलन शाह के मुंबई दौरे का दूसरा प्रमुख कार्यक्रम नवी मुंबई के वाशी में आयोजित होने वाला अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन होगा। गणेशोत्सव के बीच 14 और 15 सितंबर को सिडको प्रदर्शनी केंद्र में छठा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सम्मेलन में प्रमुख अतिथि के रूप में शामिल होंगे। सम्मेलन में देशभर से हिंदी के साहित्यकार, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि, अधिकारी और अन्य प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्री एवं अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रह सकते हैं।

कर्नाटक में मंत्री सतीश जारकीहोली और उनसे जुड़े परिसरों पर ईडी का छापा

सीएम शिवकुमार बोले- यह कार्रवाई राजनीतिक रूप से प्रेरित, कांग्रेस डरने वाली नहीं

बेंगलुरु।

कर्नाटक में मंत्री सतीश जारकीहोली और उनसे जुड़े परिसरों पर ईडी की छापेमारी को लेकर सीएम डीके शिवकुमार ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया और कहा कि सरकार के 100 दिन पूरे होने से ठीक पहले इस तरह की कार्रवाई के लिए समय का राजनीतिक फायदा उठाया जा रहा है। शिवकुमार ने कहा कि ईडी चाहे उनके कितने भी लोगों के खिलाफ छापेमारी करे, कांग्रेस इससे घबराने वाली नहीं है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईडी की कई स्थानों पर चल रही छापेमारी पर सीएम शिवकुमार ने कहा कि सतीश जारकीहोली के खिलाफ बुधवार को की गई कार्रवाई राजनीतिक रूप से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि सरकार के 100 दिन पूरे होने वाले हैं और एजेंसियों की कार्रवाई के समय का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि सतीश जारकीहोली के खिलाफ ईडी की कार्रवाई कोई ऐसी बात नहीं है, जिसकी जानकारी सरकार को पहले से नहीं थी। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी उनके खिलाफ ईडी की छापेमारी हो चुकी है। शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों को घबराने की जरूरत नहीं। कर्नाटक के सीएम ने बीजेपी पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी राजनीतिक रूप से एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इससे पहले बी नागेंद्र के खिलाफ भी ईडी की छापेमारी की गई थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है। सीएम ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस नेता प्रियंक खड़गे भी हैं और कर्नाटक लोक सेवा आयोग के मुद्दे को लेकर उन्हें भी निशाना बनाया जा रहा है।

तस्करी कर लाए गए औरंगुटान के 5 बच्चे

अंतरराष्ट्रीय बाजार में 20 से 25 लाख रुपये कीमत

बालासोर ।

ओडिशा के बालासोर जिले के बिचित्रपुर जंगल में मंगलवार सुबह औरंगुटान के पांच बच्चे मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार, ये जानवर भारत में नहीं पाए जाते हैं। औरंगुटान मुख्य रूप से इंडोनेशिया, मलेशिया, बोर्नियो और सुमात्रा के जंगलों में पाए जाते हैं। आशंका जताई जा रही है कि इन्हें तस्करी के जरिए भारत लाया गया होगा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक औरंगुटान की कीमत करीब 20 से 25 लाख रुपये तक बताई जाती है।

जंगल में पांचों बच्चों के मिलने के बाद वन विभाग और प्रशासन में भी हलचल बढ़ गई। राज्य सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं।

प्रदर्शन में शामिल जीबीयू छात्र को 5 लाख का नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- कार्रवाई कैसे हुई?

सीजेआई सूर्यकांत ने डीएम से मांगा जवाब

जंतर-मंतर प्रदर्शन में शामिल होने पर जारी हुआ था शांति बंधपत्र का नोटिस

ग्रेटर नोएडा ।

गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी (जीबीयू) के छात्र अक्षय त्रिपाठी को जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन में शामिल होने के मामले में जारी 5 लाख रुपये के नोटिस का विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मामले का उल्लेख चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत के समक्ष किया गया। इस पर सीजेआई ने कहा कि वह गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी से मामले में जवाब मांगेंगे।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 1 सितंबर के अदालत के आदेश के बावजूद छात्र के खिलाफ कार्रवाई की गई। उन्होंने इसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना बताते हुए कहा कि इसका प्रभाव देशभर में प्रदर्शन में शामिल होने वाले छात्रों पर पड़ सकता है। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि अदालत के आदेश में स्पष्ट किया गया था कि प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने मामले में गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी से जवाब लेने की बात कही। 5 लाख रुपये के बॉन्ड का दिया गया था नोटिस पुलिस रिपोर्ट के आधार पर 4 सितंबर को कार्यकारी मजिस्ट्रेट, ग्रेटर नोएडा की ओर से अक्षय त्रिपाठी को नोटिस जारी किया गया था। इसमें छह महीने तक शांति बनाए रखने के लिए 5 लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की दो जमानतें देने को कहा गया था। नोटिस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 130 के तहत जारी किया गया था। पुलिस का आरोप था कि अक्षय छात्रों को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे और ऐसी जानकारी प्रसारित कर रहे थे, जिससे सार्वजनिक शांति और कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका थी।

पुलिस ने वापस लिया नोटिस

मामला सामने आने के बाद पुलिस के अनुसार 4 सितंबर को ही नोटिस वापस ले लिया गया था। हालांकि, याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाया गया कि जब अदालत ने प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था, तो नोटिस जारी कैसे किया गया।

हाई कोर्ट ने रद्द किया ट्रायल कोर्ट का फैसला

खड़गे परिवार के ट्रस्ट को जमीन आवंटन मामले की नहीं होगी जांच

बेंगलुरु।

कर्नाटक हाई कोर्ट ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार द्वारा संचालित ट्रस्ट को बेंगलुरु विकास प्राधिकरण की जमीन आवंटित किए जाने में कथित अनियमितताओं की जांच से जुड़े मामले में अहम फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने आरोपों की जांच करने के लिए गठित स्पेशल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। यह मामला 8,001 वर्ग मीटर की बेशकीमती जमीन के आवंटन से जुड़ा है।

इस मामले में शिकायतकर्ता ने पुलिस जांच की मांग की थी। उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर विशेष अदालत के उस फैसले को चुनौती दी, जिसमें अदालत ने खुद जांच शुरू करने का फैसला किया था। मामला बेंगलुरु विकास प्राधिकरण की ओर से सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को दी गई 8,001 वर्ग मीटर की बेशकीमती जमीन के आवंटन से जुड़ा है।

18 अगस्त के अपने फैसले में हाई कोर्ट ने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों से जुड़े मामलों की अदालत ने खुद जांच शुरू करके गलती की।

शिकायतकर्ता विजयराघव मराठे ने पुलिस जांच की मांग करते समय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया था। इसके बावजूद निचली अदालत ने मामले में खुद जांच शुरू कर दी।

सत्य निकेतन हादसे के बाद दिल्ली में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन,कई इलाकों में कार्रवाई

सीएम रेखा गुप्ता ने एमसीडी को दिए सख्त निर्देश; अशोक नगर, लक्ष्मी नगर और पांडव नगर में चलेगा अभियान, पीजी हॉस्टलों की भी होगी जांच

नई दिल्ली।

दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में इमारत गिरने की घटना के बाद अवैध और अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई तेज हो गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अधिकारियों को नियमों का उल्लंघन कर किए गए निर्माण के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद बुधवार को अशोक नगर, लक्ष्मी नगर, पांडव नगर समेत दिल्ली के कई इलाकों में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। अभियान के दौरान एमसीडी के वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर मौजूद रहने और कार्रवाई की निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को दिल्ली के सभी पीजी हॉस्टलों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बिल्डिंग रिकॉर्ड की जांच कर यह पता लगाया जाए कि संबंधित अवैध निर्माण कब हुआ और उस समय किस अधिकारी या विभाग के अधिकार क्षेत्र में था। जहां अवैध निर्माण पाया जाए, वहां नियमों के मुताबिक कार्रवाई करने को कहा गया है।

12 जोन में 35 इमारतों पर कार्रवाई सत्य निकेतन हादसे के बाद एमसीडी ने अनधिकृत और असुरक्षित इमारतों के खिलाफ अभियान तेज किया है। मंगलवार को निगम के 12 जोन में कुल 35 इमारतों को ध्वस्त किया गया। रोहिणी में छह, नरेला में तीन, सिविल लाइंस में तीन और शाहदरा नॉर्थ में छह इमारतों पर कार्रवाई की गई। करोल बाग के बड़े गोदामों में भी निगम ने कार्रवाई की।

तीन महीने में 983 संपत्तियों पर चला बुलडोजर एमसीडी के आंकड़ों के मुताबिक, 1 जून से 3 सितंबर 2026 के बीच 983 संपत्तियों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, 464 संपत्तियों को सील और अनधिकृत निर्माण के संबंध में 1,516 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। इस अवधि में ध्वस्तीकरण से जुड़े 726 आदेश भी जारी हुए। इसके अलावा आवासीय संपत्तियों के व्यावसायिक इस्तेमाल की पहचान के लिए एमसीडी ने तीन महीने तक सर्वे किया। इस दौरान 404 कॉलोनियों और 168 वार्डों में करीब 3 लाख संपत्तियों का सर्वे किया गया।

राम मंदिर ट्रस्ट से हटाए गए 'खास' कर्मचारियों की वापसी शुरु

अयोध्या।

अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए महासचिव स्वामी गोविंददेव गिरि के कार्यभार संभालने के बाद मंदिर की व्यवस्थाओं में बदलाव किए गए हैं। अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन के कार्यकाल में हटाए गए या दूसरी जगह भेजे गए कई 'खास' कर्मचारियों की पुराने पदों और दायित्वों पर वापसी शुरू हो गई है। इनमें पूर्व ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा और ट्रस्ट से जुड़े अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों के करीबी माने जाने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चंदा चोरी की शिकायतों के बाद महासचिव चंपत राय के इस्तीफे के बाद कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव की जिम्मेदारी दी गई थी। गोपाल राव के करीबी बताए जाने वाले सोमेश अलंदी को तीर्थ क्षेत्र पुरम से वापस राम मंदिर में तैनाती देने का आदेश जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने अभी राम मंदिर में ज्वाइन नहीं किया है और तीर्थ क्षेत्र पुरम में ही हैं।

राहुल गांधी के जनता दरबार में उमड़ी भीड़, लोगों ने रखीं समस्याएं

- सपा नेताओं, कार्यकर्ताओं ने भी की मुलाकात

रायबरेली।

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के रायबरेली दौरे के अंतिम दिन बुधवार को भुएमऊ गेस्ट हाउस में आयोजित जनता दरबार में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। सुबह करीब नौ बजे शुरू हुए जनता दरबार में राहुल गांधी ने लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं और मांगें सुनीं। गेस्ट हाउस के बाहर लोगों की लंबी कतार लगी रही। सुरक्षा व्यवस्था के तहत लोगों को एक-एक कर अंदर प्रवेश दिया गया।

जनता दरबार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ आम नागरिकों और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी भी देखने को मिली।

सपा नेताओं ने राहुल गांधी के सामने स्थानीय और क्षेत्रीय मुद्दे रखे।

इससे रायबरेली में कांग्रेस और सपा के बीच राजनीतिक समन्वय की तस्वीर सामने आई। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश सचिव अखिलेश माही ने राहुल गांधी से मुलाकात कर वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए रायबरेली के राजेंद्र यादव के नाम पर स्मारक और चौराहा बनवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि देश की सेवा करते हुए शहीद हुए राजेंद्र यादव के नाम पर अब तक जिले में प्रतिमा या स्मारक नहीं बनाया गया है। माही के अनुसार, राहुल गांधी ने उनकी मांग पर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगा और भाजपा को कड़ी चुनौती दी जाएगी।

महिला कांग्रेस पदाधिकारियों ने बांधी राखी

जनता दरबार में महिला कांग्रेस की पदाधिकारियों ने भी राहुल गांधी से मुलाकात की। रायबरेली महिला कांग्रेस अध्यक्ष लक्ष्मी सिन्हा ने राहुल गांधी को राखी बांधी और तिलक लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वर्ष 2029 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कार्यकर्ता पूरी ताकत से जुटे हैं।

मिश्रा ने ज्ञापन सौंपा

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के अध्यक्ष अनिल मिश्रा ने भी राहुल गांधी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों की कुर्बानियों को संरक्षित करने तथा मुंशीगंज शहीद स्मारक के अधूरे सौंदर्यीकरण कार्य को जल्द पूरा कराने की मांग की।

सर्राफा कारोबारियों ने उठाया जीएसटी का मुद्दा

राहुल गांधी के दौरे के दौरान मंगलवार रात सर्राफा कारोबारियों के साथ हुई बैठक भी चर्चा में रही। प्रभु टाउन में कारोबारी फाना त्रिवेदी के आवास पर हुई बैठक में व्यापारियों ने सोने-चांदी के कारोबार में करीब 50 प्रतिशत गिरावट का मुद्दा उठाया। कारोबारियों ने कहा कि इससे उनका व्यवसाय प्रभावित हो रहा है।

राहुल गांधी ने भरोसा दिलाया कि सोने-चांदी पर बढ़े जीएसटी का मुद्दा संसद में उठाया जाएगा।

सांसद निधि की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण

राहुल गांधी अपने दौरे के अंतिम दिन सांसद निधि से करीब तीन करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 12 बजे बचत भवन में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में शामिल होंगे।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

हनीट्रेप के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है आइएसआइ

(लेखक- मनोज कुमार अग्रवाल)

पड़ोसी दुश्मन देशों की खुफिया एजेंसियां सोशल मीडिया के जरिए भारतीय सुरक्षा बलों और रक्षा संस्थानों के अधिकारियों को हनी ट्रैप में फंसाकर संवेदनशील जानकारियां जुटा रही हैं। सीमा पार से जारी छद्म युद्ध अब केवल गोलियों और बमों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह डिजिटल स्पेस और मानव मन के सूक्ष्म पहलुओं तक फैल चुका है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए अब एक नए और अत्यंत खतरनाक हथियार प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिकों द्वारा संचालित डिजिटल हनी-ट्रैप का इस्तेमाल कर रही है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की गतिविधियां लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय रही हैं। समय के साथ उसके तौर-तरीके भी बदल रहे हैं। पहले जासूसी के लिए धन, लालच, दबाव और धमकी जैसे हथकंडों का इस्तेमाल अधिक होता था लेकिन आईएसआई अब संवेदनशील पदों पर बैठे अधिकारियों की पहचान कर उनकी मानसिक और भावनात्मक कमजोरियों का अध्ययन करने के लिए प्रशिक्षित लोगों की सहायता ले रही है। महिलाओं के नाम से फर्जी सोशल मीडिया खाते बनाकर पहले संपर्क स्थापित किया जाता है और धीरे-धीरे भरोसे का रिश्ता तैयार किया जाता है। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि इस नए जाल में सीधे पैसे का लालच देना जरूरी नहीं रह गया है। किसी अधिकारी की निजी परेशानी, अकेलापन, वैवाहिक तनाव, कार्यस्थल की नाराजगी या भावनात्मक असंतोष को हथियार बनाया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर अपनी निराशा, तनाव या निजी समस्याओं को लगातार साझा करता है तो वह अनजाने में अपने बारे में ऐसी सूचनाएं सार्वजनिक कर देता है, जिनका इस्तेमाल उसे प्रभावित करने में किया जा सकता है। कभी किसी एप्लिकेशन को मोबाइल या कंप्यूटर में इंस्टॉल करने को कहा जाता है। संदिग्ध ऐप और सॉफ्टवेयर इस जासूसी तंत्र का दूसरा बड़ा हथियार हैं। भारत में पहले भी रक्षा और संवेदनशील संस्थानों से जुड़े व्यक्तियों के हनी ट्रैप में फंसने के आरोप सामने आते रहे हैं। डीआरडीओ के पूर्व वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर से जुड़ा मामला विशेष रूप से चर्चा में रहा था।

हाल ही में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर को पाकिस्तानी खुफिया ऑपरेटिव द्वारा रचे गए ऐसे ही एक डिजिटल हनी ट्रैप जाल में गोपनीय जानकारी साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हनी ट्रैप और जासूसी का नया तरीकाफर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल- दुश्मन देश के हैंडलर्स महिलाओं या आकर्षक नामों से फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर फर्जी आईडी बनाकर अधिकारियों से दोस्ती करते हैं। बातचीत, चैट और वीडियो कॉल के जरिए पहले विश्वास जीता जाता है, फिर निजी पलों या तस्वीरों के बहाने ब्लैकमेल या प्रलोभन का खेल शुरू होता है।जासूसी के मामलों में कई बार अधिकारियों के फोन में रिमोट एक्सेस मैलवेयर या स्पाईवेयर तक इंस्टॉल करवाने की कोशिश की जाती है ताकि गुप्त डेटा स्वतः ट्रांसफर होता रहे। ऐसे मामलों में पकड़े जाने पर आरोपियों के खिलाफ आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत गंभीर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं।

दिल्ली पुलिस ने भारतीय वायुसेना के एक विंग कमांडर को कथित पाकिस्तानी हनी ट्रैप मामले में गिरफ्तार किया है। वायुसेना से आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद अधिकारी के खिलाफ आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।

पुलिस के अनुसार, मामले की शुरुआत सोशल मीडिया के जरिए हुई एक कथित दोस्ती से हुई। एक महिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से विंग कमांडर से संपर्क किया। बातचीत आगे बढ़ने के साथ दोनों के बीच चैट और वीडियो कॉल के जरिए लगातार संपर्क होने लगा। जांच एजेंसियों का आरोप है कि महिला ने धीरे-धीरे अधिकारी का विश्वास हासिल किया और इसके बाद उससे सैन्य गतिविधियों तथा रक्षा प्रतिष्ठानों से जुड़ी संवेदनशील जानकारी मांगनी शुरू कर दी।

दिल्ली पुलिस को यह मामला भारतीय वायुसेना की खुफिया शाखा से मिली विशिष्ट जानकारी के आधार पर सामने आया। पुलिस ने विंग कमांडर को 30 मई की रात गिरफ्तार किया। जांच के दौरान उसके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, डिजिटल बातचीत और अन्य संभावित साक्ष्यों की पड़ताल की गई। पुलिस ने 7 जुलाई को जांच पूरी करने के बाद अदालत में आरोपपत्र भी दाखिल कर दिया है।

भारतीय सेना, रक्षा अनुसंधान संगठन और संवेदनशील सरकारी विभागों की सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी आई. एस. आई. द्वारा हनी ट्रैप के हथकंडे का लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है।

इसके लिए पाकिस्तानी महिला एजेंट भारतीय सेना के चंद अधिकारियों तथा आम लोगों को बोगस नामों से वीडियो काल करके अश्लील हरकतों द्वारा उन्हें भी ऐसा ही करने के लिए उकसाती हैं और सोशल मीडिया के जरिए उनके रूप जाल में फंस कर ये लोग भारतीय सेना की महत्वपूर्ण जानकारियां उन्हें देकर देश से गद्दारी कर रहे हैं जिनकी इसी वर्ष कई मामले सामने आए हैं 4 जनवरी को अम्बाला (हरियाणा) में हनी ट्रैप का शिकार होकर भारतीय सेना की यूनिटों की लोकेशन, मूवमैंट और तैनाती से जुड़ी गुप्त जानकारी पाकिस्तान भेजने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया गया। उसके मोबाइल से व्हाट्सएप चैट व वायस काल से जुड़े महत्वपूर्ण प्रमाण मिले।11 मार्च को लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में स्वयं को कीर्ति कुमारी बताने वाली एक पाकिस्तानी महिला एजेंट द्वारा हनी ट्रैप में फंसाए गए भारतीय वायुसेना के लांस नायक आदर्श कुमार उर्फ लक्की को युद्धपोत आई. एन. एस. विक्रांत तथा आई. एन. एस. इक्षक की फोटो व अन्य जानकारी भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

इससे पूर्व इसी पाकिस्तानी एजेंट ने गोवा में नौसेना के शिपयार्ड पर पार्ट टाइम नौकरी करने वाले राम सिंह को अपने रूप जाल में फंसाकर उससे शिपयार्ड पर आने वाले युद्धपोतों के फोटो व अन्य जानकारियां प्राप्त की थीं।

22 मार्च को चाबुआ (असम) में हनी ट्रैप में फंसे भारतीय वायुसेना स्टेशन के मल्टी-टास्कर्स स्टाफ के सदस्य सुमित कुमार को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने और संवेदनशील रक्षा जानकारी सांझा करने के आरोप में राजस्थान इंटेलीजेंस और वायुसेना इंटैलीजैंस ने मिलकर गिरफ्तार किया।पाकिस्तानी हैंडलर्स ने सुमित कुमार को हनी ट्रैप में फंसा कर और पैसों का लालच देकर सुखोई फाइटर जैट्स, मिसाइल सिस्टम और सैन्य ठिकानों की संवेदनशील लोकेशनों की जानकारी पाने के लिए इस्तेमाल किया था।

1 जून को जम्मू-कश्मीर पुलिस तथा सेना के एक संयुक्त अभियान के दौरान जम्मू जिले के सतवारी इलाके से एक युवक को पाकिस्तान की एक महिला एजेंट को प्रतिरक्षा संस्थानों के फोटो सांझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

पुलिस के अनुसार उसे एक महिला ने स्वयं को सुंदरबनी में तैनात बी.एस.एफ. की कर्मचारी बता कर अपने जाल में फंसाया। जांच में पुष्टि हुई कि उक्त युवक ने चंद रुपयों के बदले में उसे फोटो भेजे थे।और अब 8 अगस्त को दिल्ली पुलिस ने संवेदनशील रक्षा जानकारी पाकिस्तान के साथ सांझा करने के आरोप में भारतीय वायुसेना के एक विंग कमांडर को आफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है।

इस अधिकारी को आई. एस. आई. की एक महिला एजैंट ने सोशल मीडिया के जरिए हनी ट्रैप में फंसा लिया था। महिला ने अधिकारी से संपर्क स्थापित करने के बाद वीडियो काल और अन्य डिजीटल माध्यमों से उससे बातचीत शुरू कर दी।

उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान सिर्फ भारतीय वायुसेना के सदस्यों को ही हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश नहीं करता बल्कि वह नौसेना तथा प्रतिरक्षा से जुड़े अन्य विभागों के कर्मचारियों व आम लोगों को भी टार्गेट करता है।

पाकिस्तान के शासकों को पता है कि भारत की सबसे बड़ी सैन्य ताकत वायुसेना है। 1999 में कारगिल युद्ध से लेकर 2019 में की गई बालाकोट स्ट्राइक और आप्रेशन सिंदूर तक भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को तगड़ी चोट दी थी। इसीलिए भारतीय वायुसेना की तैयारी और तैनाती की जानकारी जुटाने के लिए पाकिस्तान भारतीय वायुसेना से जुड़े लोगों को खास तौर पर निशाना बना रहा है।

निश्चय ही राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ऑनलाइन हनी ट्रैप बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है अतः इसके लिए भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठानों में निगरानी बढ़ाने तथा पकड़े जाने वाले दोषियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें जल्द से जल्द कठोरतम दंड देने की आवश्यकता है ताकि उससे दूसरों को भी सबक मिले।हनीट्रेप से बचना चाहिए इसके लिए सावधानी जरूरी है लगातार सभी सैन्य यूनिटों को आगाह किया जाता है कि वह किसी भी आकर्षण से बचें और देश की सुरक्षा के लिए खतरा न बने इसके लिए अपरिचित फ्रेंड रिक्वेस्ट से बचें- सोशल मीडिया पर किसी भी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करें। अपनी तैनाती, ड्यूटी रोस्टर, ऑफिस के काम या यात्रा योजनाओं की चर्चा ऑनलाइन बिल्कुल न करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या प्रलोभन भरे संदेश की सूचना तुरंत अपने विभाग या संबंधित सुरक्षा एजेंसी को दें। (लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं पिछले 40 वर्ष से लेखन और पत्रकारिता से जुड़े हैं)

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

संपादकीय

बेलगाम अधिकारी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय की एक छात्रा को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत अनावश्यक रूप से गिरफ्तार करने के मामले जो टिप्पणियां की हैं, वो देश में राज्य सरकारों के लिये एक गंभीर चेतावनी समझी जानी चाहिए। अदालत ने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को इस मामले में कड़ी फटकार लगाते हुए अफसरों के रवैये को तानाशाही वाला बताया है। कोर्ट ने बेहद सख्त भाषा का प्रयोग करते हुए राज्य को ऐसी जगह बताया जहां सरकार का निरंकुश नियंत्रण कानून-व्यवस्था के मामले में हो। स्पष्ट शब्दों में अदालत ने इस घटनाक्रम को मनमाने ढंग से आजादी छीनने वाला बताया। निश्चित रूप से, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार छात्रा की हिरासत को रद्द करने का कोर्ट का फैसला कई गंभीर प्रश्नों को भी जन्म देता है। जो यह भी दर्शाता है कि अधिकारियों द्वारा असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल किस तरह से एक सामान्य मामले में किया जा रहा है। निस्संदेह, इसमें दो राय नहीं कि एहतियाती तौर पर हिरासत में लेना एक असाधारण उपाय है। लेकिन इस गिरफ्तारी को तभी सही ठहराया जा सकता है जब इसे सिद्ध करने के लिये पुख्ता सबूत हों। यानी कि कोई व्यक्ति वास्तव में देश की सार्वजनिक व्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये गंभीर खतरा हो। दूसरे शब्दों में कहें तो यह सामान्य आपराधिक कानून का आसान विकल्प या असहमति की आवाज को दबाने का जरिया नहीं बन सकता है। बताया जाता है कि इस प्रकरण में, खबरों के अनुसार अदालत को कोई ऐसा ठोस सबूत पुलिस उपलब्ध नहीं करा सकी, जिससे यह साबित होता हो कि छात्रा का हिंसा भड़काने में कोई सीधा संबंध रहा हो। उल्लेखनीय है कि मामले में लिप्त अधिकारी कोई ऐसा ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके, मसलन व्हाट्स ऐप संदेश या वीडियो उपलब्ध नहीं करा सके, जो यह साबित करता कि छात्रा ने लोगों को दंगे या तोड़-फोड़ के लिये उकसाया था। जिसके बाद ही अदालत ने अभियुक्त की हिरासत रद्द करने के आदेश दिए। देश का स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास इस बात का गवाह है कि लोकतांत्रिक ढंग से विरोध करना एक जायज अधिकार रहा है। एक स्वतंत्र देश में तो यह अधिकार और सबल हो जाता है। निस्संदेह, किसी संवैधानिक लोकतंत्र में विरोध व प्रदर्शन में शामिल होने और हिंसा भड़काने के बीच फर्क बहुत अहम है। इससे भी ज्यादा चिंता की बात प्रशासनिक प्रक्रिया के बारे में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की सख्त टिप्पणियां हैं। दरअसल, अदालत ने गिरफ्तारी के समय और आधिकारिक रिकॉर्ड तैयार करने के दौरान सामने आई विसंगतियों पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने इस प्रक्रिया को घटना के बाद रची गई कार्रवाई जैसा बताया है। इस घटनाक्रम का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू कोर्ट द्वारा दिया गया निर्देश है कि घटनाक्रम के लिये जिम्मेदार अधिकारियों से पांच लाख रुपये का मुआवजा वसूला जाए। इतना ही नहीं अधिकारियों के सर्विस रिकॉर्ड में इस बाबत टिप्पणी दर्ज की जाने का निर्देश दिया गया है। अदालत की सोच रही है कि जब कोई भी अधिकारी सरकारी ताकत का गलत ढंग से इस्तेमाल करता है, तो जवाबदेही सिर्फ सरकारी खजाने तक ही सीमित नहीं रह सकती है। जिसका निहितार्थ यह भी है कि सरकारी कर्मचारी जबर्दस्ती प्रयोग की जाने वाली ताकत के मालिक नहीं हैं, वरन सही मायने में वे उसके संरक्षक होते हैं। वास्तव में उनकी निष्ठा सत्ता के बजाय संविधान और कानून के प्रति ईमानदारी से होनी ही चाहिए।

हमारी आंगनवाड़ी- हमारी जिम्मेदारी है, तो जवाबदेही किसकी?

(लेखक - सुनील कुमार गुप्ता)

राष्ट्रीय पोषण माह शुरू, कुछ जरूरी सवाल

-समुदाय की जिम्मेदारी, सरकार की जवाबदेही का विकल्प नहीं हो सकती

आज बुधवार 9 सितंबर से देश में नौवां राष्ट्रीय पोषण माह शुरू हो गया है। इस साल यानी 2026 की थीम है 'हमारी आंगनवाड़ी, हमारी जिम्मेदारी'। थीम बहुत आकर्षक है। इस बार भी पूरे महीने पोषण को लेकर हंसते खिल-खिलाते बच्चों-महिलाओं के पोस्टर लगेंगे। पोषण मेले लगेंगे, आंगनबाड़ी सजेंगी, रैलियां होंगी, पोषण के सहज उपलब्ध स्थानीय खाद्य पदार्थों और प्रोटीन पर चर्चा होगी, लेकिन इसके साथ एक असुविधाजनक सवाल भी पूछा जाना चाहिए, पहला- हमारी आंगनवाड़ी-हमारी जिम्मेदारी है, तो जवाबदेही किसकी है? दूसरा- क्या पोषण का काम केवल 'अभियान' है या रोज का सार्वजनिक काम? आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी है तो उन महिलाओं यानी आंगनवाड़ी या आशा कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी किसकी है, जो गांव-गांव जाकर इस पूरी व्यवस्था को चलाती हैं और जिन्हें कई बार महीनों मानदेय नहीं मिलता और मजबूरन काम छोड़ आंदोलन के लिए सड़क पर उतरना पड़ता है?

इस साल सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों में साप्ताहिक मेन्यू में विविधता, स्थानीय खाद्य पदार्थों, दालों, अनाज, मिलेट, मौसमी सब्जियों आदि पर जोर दिया है। सामुदायिक स्वाद-परीक्षण और भोजन की गुणवत्ता पर निगरानी की भी बात है। यह महत्वपूर्ण और सराहनीय कदम है, लेकिन इसके साथ ही सवाल है—क्या एक महीने की गतिविधियों से पोषण सुधरेगा, या इसके लिए पूरे साल काम करने वाली मजबूत स्थानीय व्यवस्था चाहिए?

मेरी नजर में कुपोषण किसी कैलेंडर का कार्यक्रम नहीं हो सकता। बच्चे को इस पोषण माह में यानी सितंबर में ही प्रोटीन की जरूरत नहीं होती। गर्भवती महिला को केवल पोषण माह में ही आयरन और उचित आहार की जरूरत नहीं होती। छह महीने के बच्चे को केवल अभियान के दौरान ही पूरक आहार की जानकारी नहीं चाहिए। समझने की बात है कि यह हर रोज, हर महीने की ज़रूरत है।

इस साल यानी 2026 की थीम तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन यह सवाल तो बनता है कि 'हमारी आंगनवाड़ी, हमारी जिम्मेदारी', लेकिन जवाबदेही किसकी? वास्तव में अगर आप देखें तो इस वर्ष की थीम का सबसे महत्वपूर्ण शब्द शायद 'हमारी' है।

सरकार चाहती है कि समुदाय आंगनवाड़ी को अपना माने। नए दिशानिर्देशों के तहत आंगनवाड़ी प्रबंधन समितियों को मजबूत करने, मेन्यू बोर्ड प्रदर्शित करने और समुदाय को भोजन एवं सेवाओं की निगरानी से जोड़ने पर जोर दिया गया है। पोषण माह के दौरान हर आंगनवाड़ी में कम-से-कम एक समिति बैठक का लक्ष्य रखा गया है। यह स्वागतयोग्य है, मगर 'सामुदायिक जिम्मेदारी' को सरकारी जिम्मेदारी का विकल्प नहीं बनाया जा सकता। समुदाय निगरानी कर सकता है, सवाल पूछ सकता है, नागरिक अधिकारों की मांग कर सकता है, स्थानीय संसाधन जुटा सकता है, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को मानदेय समय पर देना, पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध कराना, प्रशिक्षण देना, पोषण सामग्री की गुणवत्ता और निरंतरता सुनिश्चित करना और स्वास्थ्य एवं महिला-बाल विकास विभागों के बीच समन्वय बनाना सरकार की संस्थागत जिम्मेदारी है।

इसी तरह आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से चुनावों, वोटरलिस्ट अपडेशन से लेकर लगातार नए-नए काम लेने के साथ यह भी पूछना होगा कि उनके पास उन कामों को करने के लिए पर्याप्त समय, प्रशिक्षण, यात्रा सहायता, डिजिटल साधन और आर्थिक सुरक्षा है या नहीं।

पोषण की लड़ाई में 'फ्रंटलाइन' शब्द का इस्तेमाल बहुत आसान है। हम आशा- आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अक्सर 'फ्रंटलाइन वर्कर' कहते हैं। यह सम्मानजनक शब्द है, लेकिन इसमें एक खतरा भी है। फ्रंटलाइन पर वही व्यक्ति होता है जो व्यवस्था की हर कमी का सामना सबसे पहले करता है। जरा सोचिए, परिवार भोजन नहीं जुटा पाता...कार्यकर्ता समझाए। बच्चा टीका नहीं लगवाता...कार्यकर्ता घर जाए। गर्भवती महिला अस्पताल नहीं जाती...कार्यकर्ता समझाए। बच्चा कुपोषित है...कार्यकर्ता निगरानी करे। डेटा पोर्टल पर अपडेट नहीं है—कार्यकर्ता दर्ज करे। पोषण माह है...कार्यक्रम भी करे, लेकिन उसका वेतन कह लीजिए या मानदेय, वो देर से आए, तो किससे शिकायत करे। सरकार और तंत्र को यह भी देना होगा, कि जिससे वह पोषण का संदेश दिलवा रहा है, वास्तव में उसका पोषण कैसा है? यही विरोधाभास हमें इस पोषण माह में देखना चाहिए।

वास्तव में फोकस पोषण माह के मेलों, प्रदर्शनियों, आयोजनों की चकाचौंध पर नहीं, पोषण की व्यवस्था और उसके मिलने की निरंतरता पर होनी चाहिए। समुदाय हो या मीडिया उसे देखना होगा, कि क्या उस केंद्र पर नियमित रूप से गर्म पका भोजन मिल रहा है? मेन्यू बोर्ड पर जो लिखा है, क्या वही भोजन बच्चों को मिल रहा है? क्या बच्चे की वृद्धि की नियमित निगरानी हो रही है? क्या तीन साल से कम उम्र के बच्चों के परिवारों तक घर-भेंट के जरिए पहुंच बनाई जा रही है? आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के बीच वास्तविक समन्वय है या केवल बैठक के रजिस्टर में? कितने बच्चे, माताएं, दिव्यांग पोषण की सेवाओं से छूट रहे हैं और क्यों?

और सबसे जरूरी—क्या इन कार्यकर्ताओं को उनका मानदेय समय पर मिल रहा है? क्योंकि इस साल की थीम 'हमारी आंगनवाड़ी, हमारी जिम्मेदारी' तभी सार्थक होगी जब 'जिम्मेदारी' का अर्थ केवल नागरिकों से और अधिक काम करवाना न हो, बल्कि सरकार की अपनी जवाबदेही को भी स्पष्ट करना हो। पोषण की थाली में दाल, अनाज, सब्जी और प्रोटीन जरूरी हैं। लेकिन उस थाली तक पहुंच बनाने वाली व्यवस्था में सम्मान, पर्याप्त संसाधन, प्रशिक्षित कार्यकर्ता और समय पर भुगतान भी उतने ही जरूरी हैं। एक कुपोषित बच्चे को केवल पौष्टिक भोजन की जरूरत नहीं होती; उसे ऐसी सार्वजनिक व्यवस्था चाहिए जो उस भोजन को उसके घर और आंगनवाड़ी तक लगातार पहुंचा सके।

इसलिए इस पोषण माह में शायद सबसे जरूरी सवाल यही है कि जब हम कहते हैं 'हमारी आंगनवाड़ी, हमारी जिम्मेदारी', तो क्या हम यह भी कहने को तैयार हैं कि उस आंगनवाड़ी तक पोषण पहुंचाने वाली आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की आजीविका भी हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है? यही सवाल इस बार पोषण माह को एक और सरकारी अभियान से आगे ले जाकर सार्वजनिक जवाबदेही का अभियान बना सकता है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार, स्तंभकार हैं)

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अ निवार्य नहीं है)

चिंतन मनन

सृष्टि के परम स्वामी कृष्ण

मनुष्य को जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण ब्रह्मांड के सभी लोकों के परम स्वामी हैं। वे सृष्टि के पूर्व थे और अपनी सृष्टि से भिन्न हैं। सारे देवता इसी भौतिक जगत में उत्पन्न हुए, किंतु कृष्ण अजन्मा हैं, फलतः वे ब्रह्मा और शिव जैसे देवताओं से भी भिन्न हैं। और चूंकि वे ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के स्रष्टा हैं अतः समस्त लोकों के परम पुरुष हैं। परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त पापकर्मों से मुक्त होना चाहिए। जैसे कि भगवद्गीता में कहा गया है, उन्हें केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है, किसी अन्य साधन से नहीं। मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण को साधारण मनुष्य न समझे।

इस जगत में शुभ या अशुभ वस्तुओं का बोध बहुत कुछ मनोधर्म है क्योंकि इस भौतिक जगत में कुछ भी शुभ नहीं है। प्रत्येक वस्तु अशुभ है। क्योंकि प्रकृति स्वयं अशुभ है। हम इसे शुभ मानने की कल्पना मात्र करते हैं। वास्तविक मंगल तो पूर्ण भक्ति और सेवाभाव से युक्त कृष्णभावनामृत पर ही निर्भर करता है। अतः यदि हम तनिक भी चाहते हैं कि हमारे कर्म शुद्ध हों, तो हमें परमेश्वर की आज्ञा से कर्म करना होगा। ऐसी आज्ञा श्रीमद्भागवत तथा श्रीमद्गीता जैसे शास्त्रों या प्रामाणिक गुरु से प्राप्त की जा सकती है। चूंकि गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है, अतः उसकी आज्ञा प्रत्यक्षतः परमेश्वर की आज्ञा होती है। गुरु, साधु तथा शाप एक ही प्रकार से आज्ञा देते हैं। इन तीनों स्रोतों में कोई विरोध नहीं होता। कर्म संपन्न करते हुए भक्त की दिव्य मनोवृत्ति वैराग्य की होती है, जिसे संन्यास कहते हैं। जैसा कि भगवद्गीता के छठे अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है कि जो भगवान का आदेश मानकर कोई कर्त्तव्य करता है और जो अपने कर्मफलों की शरण ग्रहण नहीं करता, वही असली संन्यासी है। जो भगवान के निर्देशानुसार कर्म करता है, वास्तव में संन्यासी और योगी वही है।

विचार मंथन

जहरीली शराब से हो रहीं मौतों के लिए कौन जिम्मेदार

(लेखक -सनत जैन)

देश में जहरीली शराब के कारण हर साल सैकड़ों की संख्या में हो रही मौत के आंकड़े साल दर साल बढ़ते चले जा रहे हैं। गुजरात, बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। जिन राज्यों में शराब बंद है, वहां पर मौत हों तो समझ में भी आता है, लेकिन जिन राज्यों में शराब का कारोबार सरकार की सरपरस्ती में होता है वहां पर यदि जहरीली शराब पीकर लोग मर रहे हैं तो इससे बड़ा अपराध सरकारों के लिए नहीं हो सकता है। लोगों तक जहरीली शराब किस तरह से पहुंच रही है? शराब कैसे जहरीली हो रही है? उनके कारण खोजने के स्थान पर जब गरीब-गुरुवा जहरीली शराब पीकर मर जाते हैं] उस समय सरकारी खजाने से कुछ राशि मुआवजे के रूप में दे दी जाती है। बड़ी-बड़ी बातें होती हैं, लेकिन जिनके ऊपर इस अपराध को रोकने की जिम्मेदारी है, वह अपने आप को बचा लेते हैं। इसका जिम्मा आबकारी विभाग और पुलिस के ऊपर छोड़कर गरीबों को मौत के मुंह में जानबूझकर ढकेलने के जो अपराधी हैं, उन पर आज तक ना तो कोई प्रश्न चिन्ह लग रहा है ना वह अपनी जिम्मेदारी मान रहे हैं। कहा जाता है इसके लिए सही मायने में सरकार में बैठे हुए नेता और अधिकारी जिम्मेदार हैं। शराब का कारोबार जब सरकार कर रही है तो यह सरकार में बैठे हुए लोगों की जिम्मेदारी है कि वह देखें शराब केवल राजस्व बढ़ाने का साधन नहीं है। देसी शराब मजदूर और गरीब आदमी पीता है। वह दिन भर मेहनत करता है, लेकिन वह नशे का आदी हो चुका है। 2004 के पहले तक राज्य सरकारें गरीबों के लिए देसी शराब के ठेके चलाती थीं। देसी शराब से कमाई के स्थान पर वह गरीबों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए पीने योग्य देसी शराब कम कीमत में उपलब्ध कराती थीं। उस समय कभी भी जहरीली शराब से मरने की खबरें नहीं आती थीं। 2004 के बाद से लगभग सभी राज्यों में देसी और विदेशी शराब अब लगभग एक ही कीमत पर बिक रही हैं। हर साल शराब महंगी होती जा रही है। गरीब सबसे ज्यादा शराब पीता है। जब उसके पास पैसा नहीं होता है तो वह कच्ची शराब भी पी लेता है।

इसके अलावा पिछले तीन-चार वर्षो में एथेनॉल के प्लांट बड़ी तेजी के साथ लगना शुरू हो गए हैं। हर जिले में अवैध तरीके से शराब बनाई जा रही है। इथेनॉल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। 1 लीटर एथेनॉल में चार बोतल शराब बन जाती है। लेकिन पानी का घनत्व हर जिले का अलग-अलग होता है, जिसके कारण जो अवैध शराब बनाकर बिक्री की जा रही है उसमें आबकारी विभाग, पुलिस विभाग और राजनेताओं का संगठित विरोध इस धंधे में काम कर रहा है। करोड़ों रुपए की कमाई हर माह शराब के अवैध कारोबार से पुलिस, आबकारी विभाग और नेताओं को हो रही है। पहले भी कच्ची शराब मेथेनॉल और एथेनॉल का उपयोग कर बनाई और बेची जाती थी, लेकिन कभी इस तरीके की घटनाएं नहीं होती थीं। अब यह घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। ऐथेनॉल पर न तो पुलिस और न ही आबकारी विभाग का जोर चलता है, ऐसे में यह आसानी से मिल जाता है। मध्य प्रदेश में जहरीली शराब से लगभग 50 लोगों की मृत्यु हो जाने की बात सामने आई है। शासन उसे स्वीकार नहीं कर रहा है। कोई 13 बताता है तो कोई 17 बताता है। गरीबों के पास काम नहीं है। शराब की उन्हें आदत लग चुकी है। देसी शराब जो पहले 20 रुपये में मिलती थी अब 75 रुपये तक में मिल रही। उस समय अंग्रेजी शराब महंगी होती थी। आज की तारीख में अंग्रेजी शराब और देसी शराब की कीमत लगभग एक ही है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकारों की नीतियां इस तरह की मौत का सबसे बड़ा कारण है। सबसे ज्यादा नशा गरीब करते हैं। सिगरेट हो, बीड़ी हो, शराब हो, तंबाकू हो यह सब मजदूर वर्ग और मेहनतकश इस तरह के नशे के आदी हो जाते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति इस तरह की नहीं होती है कि वह इसका खर्च उठा पाएं, ऐसे में वह हमेशा सस्ता विकल्प देखते हैं। देसी शराब के रूप में जो सस्ता विकल्प था वह खत्म हो गया है।

केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा जिस तरह से गुटका, तंबाकू, सिगरेट और शराब में भारी टैक्स लगाया जाता है उसके बीच में सरकारों द्वारा यह दलील दी जाती है कि इनको रोकना है। यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सरकार आंखों में पट्टी बांधकर रखती हैं। साल दर साल इनकी खपत बढ़ती ही जा रही है। सरकारी खजाने में राजस्व बढ़ता चला जा रहा है। वेध और अवैध रूप से नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेती है। जब कभी इस तरह की घटनायें हो जाती हैं, उस समय पुलिस और आबकारी विभाग के कर्मचारियों पर ठीकरा फोड़कर अपने आपको बचा लेती हैं। यह स्थिति ठीक नहीं है। नशा अनादि काल से होता रहा है। देवता भी सोम रस का सेवन करते रहे हैं। हर व्यक्ति का अपना कोई नशा होता है लेकिन पहले गरीब और अमीर के नशे में जो भेद था अब वह खत्म हो गया है। अब सबसे ज्यादा नशे के कारोबार में गरीबों से कमाई हो रही है और गरीबों को लूटने का कोई भी मौका केंद्र और राज्य सरकारें नहीं छोड़ रही हैं। जिसके कारण स्थिति दिन प्रतिदिन नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं, कुछ दिनों तक हो हल्ला मचता है। उसके बाद नशे के इस कारोबार में संगठित माफिया कमाई करता रहता है। राजनीतिक संरक्षण में यह सारा कारोबार चल रहा है। इसके लिए सही मायने में सरकार में बैठे हुए मंत्री और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सोने का भाव 399 रुपए लुढ़का, चांदी 193 रुपए चढ़ी

सोना 1,52,350 रुपए प्र ति दस ग्राम, चांदी 2,39,700 रुपए प्रति किलो

नई दिल्ली ।

कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गई हैं, जिससे महंगाई और ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका गहरा गई है। इस परिदृश्य का असर बुलियन बाजार पर भी दिख रहा है, जहां निवेशकों की भावनाएं मिश्रित हैं। बुधवार को जहां सोने में गिरावट दर्ज की गई, वहीं चांदी में मिलाजुला रुख देखने को मिला, जिसमें घरेलू बाजार में तेजी और अंतरराष्ट्रीय बाजार में नरमी रही। महंगाई की चिंता और ब्याज दरें बढ़ने की उम्मीद सोने पर दबाव डाल रही है। हालांकि, आर्थिक अनिश्चितता के इस माहौल में महंगाई से बचाव के साधन के रूप में सोने की मांग बनी हुई है। अगस्त माह में निवेश और हेजिंग मांग बढ़ने के साथ-साथ चीन समेत कई केंद्रीय बैंकों की लगातार खरीदारी ने सोने को एक मजबूत सहारा दिया था। लेकिन बुधवार को ग्लोबल मार्केट कॉमेक्स पर सोना लगभग 4,415 डॉलर प्रति औंस के करीब कारोबार कर रहा था, जिसमें 22 डॉलर से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। घरेलू बाजार एमसीएक्स पर भी सोने का अक्टूबर वायदा कॉन्ट्रैक्ट खबर लिखे जाने के समय 1,52,350 रुपये के स्तर पर 200 रुपये से अधिक की नरमी के साथ ट्रेड कर रहा था। एमसीएक्स पर सोने के वायदा भाव की शुरुआत गिरावट के साथ हुई थी, जहां बेंचमार्क अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट 399 रुपये की गिरावट के साथ 1,52,180 रुपये के भाव पर खुला था। वहीं चांदी के बाजार में बुधवार को अलग तस्वीर देखने को मिली। घरेलू वायदा बाजार एमसीएक्स पर चांदी का दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 270 रुपये से अधिक की तेजी के साथ 2,39,700 रुपये प्रति किलो के करीब कारोबार कर रहा था। यह कॉन्ट्रैक्ट 193 रुपये की तेजी के साथ 2,39,620 रुपये पर खुला था। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स पर चांदी 66.60 डॉलर प्रति औंस के आसपास हल्की गिरावट के साथ कारोबार कर रही थी, जो वैश्विक बाजार में बुलियन की चाल में अंतर को दर्शाता है।

अमेरिका ने कनाडाई डेयरी, पेय पदार्थ और मोटरसाइकिलों पर प्रतिबंध की घोषणा की

- जवाबी शुल्क के बाद ट्रंप का पलटवार, सरकारी खरीद से भी बाहर होंगे कनाडाई उत्पाद

टोरंटो ।

अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापार युद्ध और तेज हो गया, जब व्हाइट हाउस ने कनाडा से आने वाले दुग्ध उत्पादों, मादक पेयों और मोटरसाइकिलों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। यह प्रतिबंध तीन सप्ताह में लागू होगा। यह कदम कनाडा द्वारा अमेरिका से आयात होने वाले 20 अरब डॉलर मूल्य के सामान पर जवाबी शुल्क लगाए जाने के कुछ ही समय बाद उठाया गया है। कनाडा की जवाबी कार्रवाई के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडाई उत्पादों को अमेरिका की बड़ी और दीर्घकालिक सरकारी खरीद से बाहर करने का भी निर्देश दिया है। यह तब तक जारी रहेगा जब तक कनाडा अमेरिकी उत्पादों के लिए पूर्ण एवं उचित पारस्परिकता की अनुमति नहीं देता। वहीं, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिका पर देश की निर्भरता कम करने के प्रयासों में तेजी लाने का संकल्प जताया है।

कार्नी ने कहा कि कनाडा अधिक आत्मनिर्भर बनने की रणनीति पर काम कर रहा है ताकि कोई भी देश उसे बंधक न बना सके।

इसी क्रम में, कनाडा यूरोपीय संघ के साथ गहरे संबंधों की संभावनाएं तलाश रहा है, जिसमें मौजूदा समझौतों का विस्तार या नई संधि पर बातचीत शामिल है। कार्नी अगले सप्ताह स्ट्रासबर्ग में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष से मिलकर यूरोपीय संसद को संबोधित करेंगे। यह विवाद दुनिया के सबसे करीबी संबंधों में से एक को झकझोर रहा है, जबकि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं और सुरक्षा संबंध गहराई से जुड़े हुए हैं।

शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद

सेंसेक्स 813, निफ्टी 203 अंक गिरा

मुंबई ।

भारतीय शेयर बाजार बुधवार को भी गिरावट पर बंद हुआ। इस प्रकार लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में बाजार गिरावट पर बंद हुआ है। इसका कारण दुनिया भर के बाजारों से मिले कमजोर संकेतों के साथ ही बिकवाली को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने के साथ ही कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंचने के कारण निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई, जिससे प्रमुख बेंचमार्क सूचकांक लाल निशान में बंद हुए हैं।

इसी कारण दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 813.35 अंक टूटकर 74,764.23 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई का निफ्टी भी 203.60 अंक नीचे आकर 23,431.50 पर बंद हुआ। सत्र की शुरुआत में ही बाजार दबाव में आ गया था, जब सेंसेक्स अपने पिछले बंद भाव 75,577.58 से 361.36 अंक गिरकर 75,216.22 पर खुला, और कारोबारी सत्र के दौरान यह अपने दिन के निम्नतम स्तर 74,764.23 तक फिसल गया गया। इसी तरह, निफ्टीभी अपने पिछले बंद 23,635.10 से 113 अंक नीचे 23,522.05 पर शुरुआत की और दिनभर के कारोबार में 23,431.50 के निचले स्तर को छुआ। इसके अलावा व्यापक बाजारों में भी कमजोरी हावी रही। निफ्टी मिडकैप और निफ्टी स्मॉलकैप सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए।सेक्टरवार प्रदर्शन की बात करें तो, निफ्टी आईटी सेक्टर को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, जिसमें 3.24 फीसदी की भारी गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा, निफ्टी रियल्टी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी क्रमश 2.23 फीसदी और 1.23 फीसदी की गिरावट देखी गई। निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी मीडिया और निफ्टी फार्मा जैसे अन्य प्रमुख सेक्टर भी गिरावट साथ बंद हुए। हालांकि, इस नकारात्मक माहौल के बीच निफ्टी मेटल इंडेक्स में 1.79 फीसदी की अच्छी तेजी दर्ज की गई, जो बाजार के लिए एक मात्र सकारात्मक संकेत रहा।

निफ्टी50 इंडेक्स में शामिल प्रमुख शेयरों में अदाणी इंटरप्राइजेज, मैक्स हेल्थ, अदाणी पोर्ट्स, कोल इंडिया, टाटा स्टील, हिंडाल्को, अपोलो हॉस्पिटल और एनटीपीसी के शेयरों में 1 से 5 फीसदी तक की बढ़त देखी गई और ये दिन के सबसे अधिक लाभ वाले शेयर रहें। । इसके विपरीत, इंफोसिस, एचडीएफसी लाइफ, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा जैसी दिग्गज कंपनियों के शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली दर्ज की गई और वे नुकसान उठाने वाली कंपनियों में सबसे आगे रहे।

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि निवेशक अब मध्य पूर्व में संभावित लंबे समय तक चलने वाले टकराव के परिणामों को ध्यान में रखकर कीमतें तय कर रहे हैं। इस लगातार जारी लड़ाई और जवाबी कार्रवाई के चक्र के कारण निकट भविष्य में कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी रहने की प्रबल संभावना है। वहीं आज सुबह बाजार की गिरावट के साथ शुरुआत हुई। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान में खुले।

कोफोर्ज चेयरपर्सन ओपी भट्ट ने दिया इस्तीफा

विवेक शर्मा बने अंतरिम अध्यक्ष

नई दिल्ली ।

आईटी सेवा कंपनी कोफोर्ज के चेयरपर्सन एवं स्वतंत्र निदेशक ओपी भट्ट ने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। उनका यह कदम आंतरिक ऑडिट में 'बोर्ड मूल्यांकन रिपोर्ट' (बीईआर) तैयार करने और पेश करने के तरीके पर गंभीर चिंताओं के सामने आने के बाद आया है। कोफोर्ज ने बताया कि आंतरिक ऑडिटर ने भट्ट के मार्गदर्शन में बोर्ड मूल्यांकन प्रक्रिया और पेश की गई रिपोर्ट की समीक्षा की, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को निदेशक मंडल से कथित तौर पर छिपाए जाने का मामला सामने आया। इस पर निदेशक मंडल ने चिंताएं जताते हुए भट्ट से स्पष्टीकरण मांगा। हालांकि, कंपनी ने कहा कि भट्ट ने उठाए गए मुद्दों पर जवाब दिया और निदेशक मंडल उनके स्पष्टीकरण पर विचार कर रहा था, इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया था। भट्ट ने कहा कि उन्होंने सद्भावना से काम किया था, लेकिन उन्होंने 8 सितंबर से तत्काल प्रभाव से बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के साथ ही भट्ट कंपनी की बोर्ड समितियों के सदस्य भी नहीं रहे। कोफोर्ज ने यह भी स्पष्ट किया कि यह मामला कंपनी के वित्तीय विवरणों या वित्तीय मामलों से संबंधित नहीं है और इसका निकट, मध्यम या दीर्घावधि में कंपनी के परिचालन या कारोबारी प्रदर्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। निदेशक मंडल ने गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक विवेक शर्मा को 31 जनवरी, 2027 तक अंतरिम चेयरपर्सन नियुक्त किया है।

गणेशोत्सव 2026: कोंकण यात्रियों को टोलमाफी का तोहफा

11 से 27 सितंबर तक निजी वाहनों व एसटी बसों को मिलेगी छूट

मुंबई ।

गणेशोत्सव 2026 के अवसर पर कोंकण स्थित अपने गांव जाने वाले लाखों गणेश भक्तों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ी राहत की घोषणा की है। राज्य सरकार ने 11 सितंबर से 27 सितंबर 2026 तक कोंकण की ओर जाने वाले गणेश भक्तों के वाहनों को टोल माफी देने का फैसला किया है। लोक निर्माण मंत्री शिवेंद्र सिंह राजे भोंसले ने इसकी जानकारी दी। यह छूट मुंबई-बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग-48, मुंबई-गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग-66 सहित लोक निर्माण विभाग और महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास महामंडल (एमएसआरडीसी) के अंतर्गत आने वाले कोंकण मार्गों पर लागू होगी। नगर विकास विभाग के अधीन अटल बिहारी वाजपेयी शिवड़ी-न्हावा शेवा अटल सेतु से कोंकण जाने वाले वाहनों को भी यह लाभ मिलेगा। सरकार का उद्देश्य है कि इससे श्रद्धालुओं पर यात्रा का अतिरिक्त आर्थिक बोझ कम हो और उनकी यात्रा सुगम बने। टोलमाफी का लाभ लेने के लिए गणेशोत्सव 2026 कोंकण दर्शन लिखे विशेष स्टिकर या पास जारी किए जाएंगे, जिन पर वाहन नंबर और चालक का नाम दर्ज होगा। ये पास पुलिस स्टेशनों, यातायात चौकियों और आरटीओ कार्यालयों सहित अन्य निर्धारित स्थानों पर उपलब्ध होंगे और वापसी में भी मान्य रहेंगे। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन महामंडल (एसटी) की कोंकण जाने वाली बसों को भी टोलमाफी मिलेगी। लोक निर्माण मंत्री भोंसले ने कहा कि गणेशोत्सव जनभावनाओं से जुड़ा त्योहार है, और सरकार का लक्ष्य भक्तों की यात्रा को सुरक्षित, सुगम व आनंददायक बनाना है।

कच्चे तेल के दाम में भारी उछाल, ब्रेंट क्रूड लगभग 100 डॉलर

अमेरिकी कच्चा तेल डब्ल्यूटीआई भी 94 डॉलर प्रति बैरल के पार

नई दिल्ली ।

वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में बुधवार को एक बार फिर जोरदार उछाल दर्ज किया गया, जिससे ब्रेंट क्रूड 100 डॉलर प्रति बैरल के बेहद करीब पहुंच गया है। अमेरिकी कच्चा तेल डब्ल्यूटीआई भी 94 डॉलर प्रति बैरल का आंकड़ा पार कर गया है। इस तेजी की मुख्य वजह पश्चिम एशिया में लगातार बढ़ता तनाव और वैश्विक तेल आपूर्ति में संभावित रुकावट का डर है। ताजा आंकड़ों के अनुसार, नवंबर डिलीवरी वाला ब्रेंट क्रूड 1.43 फीसदी चढ़कर 99.32 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया, जबकि कारोबार के दौरान यह 99.66 डॉलर तक भी गया।

इसी तरह, अक्टूबर डिलीवरी वाला डब्ल्यूटीआई क्रूड 1.34 फीसदी की तेजी के साथ 94.28 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था, जो आज 94.78 डॉलर तक पहुंचा। इस अचानक तेजी के पीछे पश्चिम एशिया में बिगड़ते हालात और सऊदी अरब के कुछ ऊर्जा ठिकानों पर हुए हमले सबसे बड़ी वजह हैं। इससे दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक सऊदी अरब से तेल आपूर्ति बाधित होने का डर बढ़ गया है। तेल बाजार की दूसरी बड़ी चिंता होर्मुज जलडमरूमध्य है, जो वैश्विक तेल व्यापार का एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है।

इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव से तेल की आवाजाही प्रभावित होने की आशंका है, जिससे आपूर्ति में कमी का डर और गहरा गया है। ब्रेंट क्रूड अब 100 डॉलर के मनोवैज्ञानिक स्तर के बेहद करीब है, लेकिन यह कहना जल्दबाजी होगी कि कीमतें लगातार बढ़ती ही रहेंगी। खाड़ी देशों द्वारा वैकल्पिक

मार्गों की तलाश और चीन की मांग में संभावित कमी जैसी बातें कीमतों की तेजी पर कुछ लगाम लगा सकती हैं।

हालांकि, फिलहाल आपूर्ति संबंधी चिंताएं हावी हैं। भारत के लिए यह स्थिति चिंताजनक है क्योंकि वह अपनी अधिकांश कच्चे तेल की जरूरत आयात से पूरी करता है। 100 डॉलर के आसपास बनी रहने वाली कच्चे तेल की कीमतें भारत के लिए आयात बिल बढ़ाएंगी, जिससे रुपये पर दबाव बढ़ सकता है और देश में महंगाई बढ़ने की आशंका भी प्रबल होगी। विमानन, पेंट, टायर और रसायन जैसे उद्योगों पर उत्पादन लागत बढ़ने का सीधा असर होगा।

फिलहाल, बाजार की नजर पश्चिम एशिया में तनाव के आगे बढ़ने और होर्मुज से तेल की आवाजाही सामान्य होने पर बनी रहेगी।

अगस्त में महंगी हुई घरेलू थाली, प्याज, तेल और रसोई गैस ने बढ़ाया बोझ

शाकाहारी थाली एक फीसदी तो मांसाहारी थाली पांच फीसदी महंगी हुई

मुंबई ।

अगस्त महीने में घरों में बनने वाले भोजन की लागत में वृद्धि दर्ज की गई है।

क्रिसिल इंटेलिजेंस द्वारा जारी नवीनतम मासिक रिपोर्ट के अनुसार, सालाना आधार पर शाकाहारी थाली की कीमत एक प्रतिशत बढ़कर 29.5 रुपये हो गई, जबकि मांसाहारी थाली पांच प्रतिशत महंगी होकर 57.5 रुपये पर पहुंच गई। रिपोर्ट बताती है कि प्याज, खाद्य तेल, चावल और रसोई गैस (एलपीजी) की ऊंची कीमतों ने थाली की लागत को ऊपर धकेला।

प्याज की कीमत सालाना आधार पर 43 प्रतिशत बढ़कर 40 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई, जिसका मुख्य कारण महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश से आपूर्ति का प्रभावित होना रहा। खाद्य तेल में 11 प्रतिशत और एलपीजी में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि, आलू की कीमत 12 प्रतिशत और टमाटर की कीमत 28 प्रतिशत घटने से कुल बढ़ोतरी सीमित रही।

मुर्गे के मांस की कीमत में 10 प्रतिशत की सालाना वृद्धि के कारण मांसाहारी थाली महंगी हुई। मासिक आधार पर, अगस्त में प्याज की कीमत 17 प्रतिशत बढ़ी, जबकि टमाटर सात प्रतिशत सस्ता हुआ। श्रावण माह के कारण मुर्गे के मांस की कीमत में चार प्रतिशत की मासिक गिरावट आई, जिससे जुलाई की तुलना में अगस्त में मांसाहारी थाली की लागत एक प्रतिशत कम रही। क्रिसिल इंटेलिजेंस के एक अे धिकारी के अनुसार रबी फसल की कम आपूर्ति और खरीफ फसल की आवक में देरी के कारण अगले दो-तीन महीनों तक प्याज की कीमतें ऊंची बनी रहने का अनुमान है।

रुपया गिरावट पर बंद

मुंबई ।

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले बुधवार को भारतीय रुपया 33 पैसे की गिरावट के साथ ही 95.07 पर बंद हुआ। आज सुबह रुपया शुरुआती कारोबार में 21 पैसे टूटकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 94.95 पर आ गया। कच्चे तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी से रुपये पर दबाव रहा। अमेरिका-ईरान के बीच जारी तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के स्तर के करीब पहुंच गई हैं। हालांकि, विदेशी मुद्रा कारोबारियों का कहना है कि डॉलर में कमजोरी ने रुपये की गिरावट को कुछ हद तक सीमित रखा है। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 94.80 पर खुला। फिर 94.95 प्रति डॉलर पर लुढ़क गया जो पिछले बंद भाव के मुकाबले 21 पैसे की गिरावट है। रुपया मंगलवार को 18 पैसे टूटकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 94.74 पर बंद हुआ था। इस बीच दुनिया की छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की स्थिति को दिखाने वाला डॉलर सूचकांक 0.03 फीसदी की गिरावट के साथ 98.76 पर आ गया।

त्योहारों पर हवाई सफर हुआ महंगा, टिकट की कीमतें आसमान पर

त्योहारों पर हवाई सफर हुआ महंगा, टिकट की कीमतें आसमान पर

कई रूट्स पर 340 फीसदी तक महंगा हुआ सफर

नई दिल्ली।

अगर आप दिवाली या दुर्गा पूजा की छुट्टियों में फ्लाइट से घर जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो अब आपको अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है। त्योहारी सीजन शुरू होते ही एयरलाइंस ने हवाई किरायों में भारी बढ़ोतरी की है। कई रूट्स पर सामान्य दिनों के मुकाबले टिकटों की कीमतें कई गुना बढ़ गई हैं, कुछ मार्गों पर यह वृद्धि 340 फीसदी तक दर्ज की गई है, जिससे यात्रियों का बजट बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हवाई किराए में इस बेतहाशा वृद्धि का असर प्रमुख रूट्स पर साफ दिख रहा है। विशेष रूप से कोलकाता-देवघर रूट पर सामान्य 2,800 रुपये का किराया बढ़कर 12,500 रुपये से अधिक हो गया है। इसी तरह, दिल्ली-पटना, जहां का टिकट आमतौर पर 3,500-4,500 रुपये में मिलता था, अब 12,500 रुपये से ऊपर पहुंच गया है। दिल्ली-अगत्ती का किराया भी 8,500 रुपये से बढ़कर 25,000 रुपये तक हो गया है, जबकि बेंगलुरु-झारसुगुड़ा का किराया 4,200 रुपये से 16,200 रुपये से अधिक हो गया है। मुंबई से बरेली और कोलकाता जैसे रूट्स पर भी किराए में भारी उछाल देखा गया है, जहां सामान्य 4,500 रुपये का टिकट अब 15,000 रुपये तक और 5,000 रुपये का टिकट 11,500-14,500 रुपये तक पहुंच गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, कम प्रतिस्पर्धा वाले मार्गों पर किराये में सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई है। इस वृद्धि के पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला, त्योहारी सीजन में हवाई यात्रा की मांग में अचानक उछाल और उपलब्ध सीटों की कमी, क्योंकि एयरलाइंस अपनी कीमतें मांग और सीटों की उपलब्धता के अनुसार निर्धारित करती हैं। दूसरा, 1 सितंबर से एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) की कीमतों में 5.46 फीसदी की वृद्धि हुई है, जिससे इसकी कीमत 121.28 रुपये प्रति लीटर हो गई है।

आर्सिल ने आईपीओ से पहले एंकर निवेशकों से 220 करोड़ जुटाए

कंपनी का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम बुधवार से खुला, 11 सितंबर को होगा बंद

नई दिल्ली ।

परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसीआईएल) ने अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) से ठीक पहले प्रमुख एंकर निवेशकों से 220 करोड़ रुपये सफलतापूर्वक जुटाए हैं। कंपनी का आईपीओ बुधवार को सार्वजनिक अभिदान के लिए खुल गया है, जिसमें बड़े संस्थागत निवेशकों ने अपनी रुचि दिखाई है। शेयर बाजार को दी गई जानकारी के अनुसार, आर्सिल ने एंकर निवेशकों को 139 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 1.58 करोड़ शेयर आवंटित किए हैं। यह मूल्य आईपीओ के 132-139 रुपये प्रति शेयर के मूल्य दायरे का ऊपरी स्तर है, जो कंपनी के प्रति निवेशकों के मजबूत विश्वास को दर्शाता है।

जिन प्रमुख निवेशकों ने इन शेयरों में निवेश किया है, उनमें गोल्डमैन सैक्स इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी, व्हाइटओक कैपिटल, बंधन म्यूचुअल फंड, जेएम फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड, ग्रो म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड, आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, बजाज लाइफ इंश्योरेंस, सोसाइटी जेनरल, बीओएफए सिक्योरिटीज यूरोप एसए और इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रैटेजीज एशिया जैसे बड़े नाम शामिल हैं।

यह आईपीओ 11 सितंबर को बंद होगा और पूरी तरह से 5.27 करोड़ शेयरों की बिक्री पेशकश (ओएफएस) पर आधारित है। इसमें कोई नए शेयर जारी नहीं किए जा रहे हैं, जिसका अर्थ है कि आर्सिल को आईपीओ से कोई प्रत्यक्ष राशि प्राप्त नहीं होगी। शेयर बिक्री से प्राप्त संपूर्ण राशि बेचने वाले शेयरधारकों को मिलेगी। आर्सिल एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी है जिसका मुख्य कार्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों की फंसी हुई परिसंपत्तियों को खरीदकर उनके समाधान और पुनर्गठन का प्रबंधन करना है।

अदाणी एयरपोर्ट्स को मिला 1 अरब डॉलर का निवेश

वैश्विक दिग्गजों ने भारत की विमानन वृद्धि पर जताया भरोसा

नई दिल्ली ।

अदाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड (एएएचएल) ने वैश्विक एवं घरेलू निवेशकों के एक समूह से लगभग 1 अरब डॉलर की नई इक्विटी पूंजी जुटाने की घोषणा की है। अल्फा वेव ग्लोबल, टेमासेक, प्रेमजी इन्वेस्ट और ब्लैकरॉक सहित प्रतिष्ठित फंडों द्वारा यह निवेश किया जा रहा है, जिससे एएएचएल का प्री-मनी मूल्यांकन लगभग 18 अरब अमेरिकी डॉलर आंका गया है। यह पूंजी भारत के हवाई अड्डा बुनियादी ढांचे के विस्तार, आधुनिकीकरण और एकीकृत हवाई अड्डा-शहरों के विकास पर केंद्रित होगी, जो देश के तेजी से बढ़ते विमानन बाजार में विश्वास को रेखांकित करता है। यह भारत के हवाई अड्डा बुनियादी ढांचा क्षेत्र में वित्तीय संस्थानों द्वारा किए जाने वाले सबसे बड़े प्राथमिक इक्विटी निवेशों में से एक है। निवेशकों ने एएएचएल के साथ तीन चरणों में नए इक्विटी शेयर खरीदने के लिए बाध्यकारी समझौते किए हैं, जिसके जुलाई 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। इन चरणों के पूरा होने के बाद, निवेशकों का समूह एएएचएल में सामूहिक रूप से लगभग 5.54 प्रतिशत हिस्सेदारी रखेगा। जुटाए गए धन का उपयोग एएएचएल के हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे के विस्तार और आधुनिकीकरण, एकीकृत हवाई अड्डा-शहर परिवेश विकसित करने और ग्राउंड हैंडलिंग सहित गैर-विमानन व्यवसायों का विस्तार करने में किया जाएगा। इन निवेशों से मंच की सालाना लगभग 20 करोड़ यात्रियों को सेवाएं देने की क्षमता बढ़ने की उम्मीद है। एएएचएल के एक गैर-कार्यकारी निदेशक ने इस साझेदारी को मंच के विस्तार में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया, जबकि कंपनी सीईओ ने एएएचएल को दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा मंच बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। अदाणी एंटरप्राइजेज की यह अनुषंगी भारत में आठ हवाई अड्डों का संचालन करती है और देश के कुल यात्री यातायात में इसकी हिस्सेदारी 23 प्रतिशत से अधिक है।

ब्रिक 2026 को मिले वैश्विक नॉलेज पार्टनर, चावल उद्योग को मिलेगी नई दिशा

आईआरआरआई, ईवाई और एसएंडपी ग्लोबल की विशेषज्ञता से राष्ट्रीय राजधानी में होगा गहन मंथन

नई दिल्ली ।

भारतीय चावल निर्यातक महासंघ (आईआरईएफ) ने भारत अंतरराष्ट्रीय चावल सम्मेलन (बीआईआरसी) 2026 के लिए तीन वैश्विक संस्थानों - अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (आईआरआरआई), ईवाई और एसएंडपी ग्लोबल को 'नॉलेज पार्टनर' बनाया है। 23 से 25 अक्टूबर, 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाला यह सम्मेलन वैश्विक चावल उद्योग के सामने मौजूद चुनौतियों और अवसरों पर गहन चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करेगा। आईआरईएफ के अनुसार, इन भागीदारों को शामिल करने का उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान (आईआरआरआई), बाजार एवं जिंस संबंधी जानकारी (एसएंडपी ग्लोबल) तथा कारोबारी रणनीति (ईवाई) जैसे विशेषज्ञता के तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक साथ लाना है। यह साझेदारी ऐसे समय में हो रही है जब वैश्विक चावल उद्योग मांग में बदलाव, कीमतों में उतार-चढ़ाव और बढ़ती लॉजिस्टिक लागत जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। सम्मेलन में वैश्विक मांग-आपूर्ति, मूल्य पूर्वानुमान, नए बाजार और टिकाऊपन जैसे विषयों पर नौ ज्ञान सत्र आयोजित किए जाएंगे। आईआरआरआई अपनी वैज्ञानिक विशेषज्ञता से चावल उत्पादन व टिकाऊपन में मदद करेगा, वहीं एसएंडपी ग्लोबल बाजार एवं जिंस संबंधी जानकारी उपलब्ध कराएगा। ईवाई अपनी कारोबारी और रणनीतिक विशेषज्ञता से इन जानकारियों को ठोस फैसलों में बदलने में सहायक होगा। इन तीनों की सहभागिता से उत्पादन से लेकर वैश्विक बाजारों और कारोबारी फैसलों तक ज्ञान की एक पूरी श्रृंखला तैयार होगी। 30 अगस्त तक, 138 देशों के 3,317 खरीदार पहले ही इस सम्मेलन के लिए पंजीकरण करा चुके हैं, जो इसकी वैश्विक प्रासंगिकता को दर्शाता है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

एशियन गेम्स में पारंपरिक नीली जर्सी में खेलेंगे खिलाड़ी

फिर बदला भारतीय हॉकी टीम की जर्सी का रंग

नई दिल्ली। विश्व कप से पहले जर्सी का रंग बदलकर नारंगी करने को लेकर मचे बवाल के बाद अब आगामी एशियाई खेलों में भारतीय हॉकी टीमें अपनी पारंपरिक नीली जर्सी में नजर आएंगी। मीडिया सूत्रों ने हॉकी इंडिया अध्यक्ष दिलीप टिर्की के हवाले से लिखा, भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने टीम किट के रंगों को लेकर विकल्प दिए थे।

इसके बाद हॉकी इंडिया ने भारतीय टीम की जर्सी के लिए नीले रंग को पहली पसंद बनाया। नारंगी रंग दूसरी पसंद है। दिलीप टिर्की ने एशियाई खेलों में हिस्सा लेने जा रहे खिलाड़ियों के लिए आयोजित विदाई समारोह से इतर कहा, ''मैंने विश्व कप से पहले भी कहा था कि टीम जर्सी का नारंगी रंग स्थायी नहीं है। इसे भविष्य में बदला भी जा सकता है। अब एशियाई खेलों में नीला रंग वापस आ गया है। टीम नीली जर्सी में खेलेगी।''

हाल ही में नीदरलैंड्स और बेल्जियम में हुए विश्व कप से ठीक पहले भारतीय हॉकी टीम की जर्सी का रंग पारंपरिक नीले से बदलकर नारंगी किये जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। मामले ने राजनीतिक मोड़ भी ले लिया था जब विपक्ष ने इस पर केंद्र सरकार को निशाना बनाया था।

विवाद तब और बढ़ गया था जब दिलीप टिर्की ने प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा था कि उनकी या कार्यकारी बोर्ड की जानकारी के बिना जर्सी का रंग बदलने का फैसला लिया गया था। जर्सी का रंग बदलने के पीछे तर्क दिया गया था कि नीली टर्फ पर नीले रंग की जर्सी में खेलने से दिक्कत आती है।

उस समय भी पूर्व कप्तान वीरेन रासकिन्हा, परगट सिंह, धनराज पिल्लै, अजित पाल सिंह समेत कई दिग्गजों ने इस फैसले पर सवाल उठाए थे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम विश्व कप में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद आठवें स्थान पर रही, जबकि महिला टीम ने पांचवां स्थान हासिल किया जो 1974 के बाद उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।

एशियन गेम्स के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम जापान रवाना

भारतीय महिला हॉकी टीम जापान के आइची-नागोया में होने वाले 20वें एशियन गेम्स के लिए रवाना हो गई। कप्तान सलीमा टेटे और कोच शोर्ड मारिन नेतृत्व में भारतीय टीम मंगलवार आठ सितंबर 2026 को बेंगलुरु से रवाना हुई। एफआईएच के लॉस एंजिल्स 2028 क्वालिफिकेशन सिस्टम के तहत, 2026 एशियन गेम्स में महिला हॉकी कॉम्पिटिशन में सबसे ऊपर रहने वाली टीम लॉस एंजिल्स 2028 के लिए ओलंपिक कोटा हासिल करेगी, बशर्ते उसने पहले किसी दूसरे रास्ते से क्वालिफाई नहीं किया हो। भारतीय टीम का मुख्य लक्ष्य स्वर्ण पदक हासिल करना और लॉस एंजिल्स में 2028 में होने वाले ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई करना होगा।

एशियन गेम्स के लिए 20 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम

गोलकीपर : सविता, बिचू देवी खारीबम।
डिफेंडर : इशिका चौधरी, सुशीला चानू पुखरामबम, लालथंतलुआंगी, ज्योति, शिल्पी डबास।
मिडफील्डर : निक्की प्रधान, साक्षी राणा, सुनीता टोप्पो, सलीमा टेटे (कप्तान), नेहा, दीपिका सोरेंग।
फॉरवर्ड : लालरेमसियामी, रुतुजा दादासो पिसल, नवनीत कौर, दीपिका, इशिका, बलजीत कौर, ब्यूटी डुंगडुंग।

सार-समाचार

आईसीसी टी20 रैंकिंग

श्री चरणी शीर्ष पर बरकरार, दीप्ति शर्मा को फायदा

दुबई। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा मंगलवार को जारी टी20 गेंदबाजों की सूची में भारत की बाएं हाथ की स्पिनर शीर्ष क्रम पर बरकरार हैं। वहीं, अनुभवी दीप्ति शर्मा को फायदा हुआ है। ताजा रैंकिंग में श्री चरणी पहले, इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टन दूसरे, इंग्लैंड की चार्ली डीन तीसरे, दक्षिण अफ्रीका की एन मल्बा चौथे और इंग्लैंड की लॉरेन बेल पांचवें स्थान पर हैं। भारत की अनुभवी स्पिनर दीप्ति शर्मा को दो स्थान का फायदा

हुआ है। दीप्ति अब छठे स्थान पर चली गई हैं। दीप्ति मौजूदा एशिया कप में शानदार फॉर्म में हैं, उन्होंने तीन मैचों में आठ विकेट लिए हैं और भारतीय टीम को सेमीफाइनल में भारत की बढ़त में अहम भूमिका निभाई है। इंग्लैंड की लिंसे स्मिथ एक स्थान के नुकसान के साथ सातवें है, और पाकिस्तान की नशरा संधु एक स्थान की नुकसान के साथ आठवें नंबर पर हैं। दक्षिण अफ्रीका की मारिजेन कैप को एक स्थान का फायदा हुआ है। वह नौवें नंबर पर हैं। पाकिस्तान की सादिया इकबाल एक स्थान के नुकसान के साथ दसवें स्थान पर हैं। इसके अलावा, एशिया कप में शानदार प्रदर्शन कर रही कुछ अन्य गेंदबाजों को भी आईसीसी रैंकिंग में फायदा मिला है।

विमेंस एशिया कप

आईसीसी ने पाक बल्लेबाज पर जुर्माना लगाया

दुबई। विमेंस एशिया कप 2026 में हांगकांग, चीन के खिलाफ सोमवार को खेले गए मुकाबले के दौरान आईसीसी आचार संहिता का उल्लंघन करने पर पाकिस्तानी बल्लेबाज गुल फिरोजा को सजा भुगतनी पड़ी है। उन पर मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही फिरोजा के खाते में एक डिमेरिट प्वाइंट जोड़ा गया। यह घटना पाकिस्तानी पारी के 5वें ओवर की है, जब फिरोजा को एलबीडब्ल्यू आउट

करार दिया गया। इसके बाद फिरोजा ने अपने बल्ले की ओर इशारा करके फैसले पर असहमति जताई। फिरोजा ने बताया कि गेंद उनके बल्ले के किनारे से लगी थी।
गुल फिरोजा को खिलाड़ियों और खिलाड़ी सहायता कर्मियों के लिए आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.8 का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया, जिसमें अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान अंपायर के फैसले पर असहमति जताना शामिल है। यह फिरोजा का 24 महीनों की अवधि में दूसरा अनुशासनात्मक अपराध है।

बैलनडीओर 2026

पीएसजी और आर्सेनल समेत ये 5 क्लब 'मेंस क्लब ऑफ द ईयर' के लिए नामित

नई दिल्ली। पेरिस सेंट-जर्मेन, आर्सेनल, बायर्न म्यूनिख, नॉर्वेजियन क्लब बोडो/ग्लिम्ट समेत ब्राजीलयन क्लब फ्लेमिंगो को बैलन डी'ओर 2026 पुरस्कार में 'मेंस क्लब ऑफ द ईयर' अवॉर्ड के लिए नामित किया गया है। 'पीएसजी' इस अवॉर्ड के मौजूदा विजेता के तौर पर रेस में शामिल है। उन्होंने

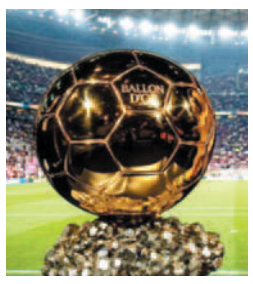

एक शानदार सीजन में अपना दूसरा चैंपियंस लीग टाइटल जीता था। उनका घरेलू और इंटरनेशनल कैंपेन भी बहुत सफल रहा, जिसमें लीग 1, फ्रेंच सुपर कप, यूरोपियन सुपर कप और इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीते। पेरिस का यह क्लब यूरोप के टॉप क्लबों में से एक के तौर पर अपनी पहचान बनाने के बाद इस सम्मान को बरकरार रखने की उम्मीद करेगा। प्रीमियर लीग टाइटल के लिए लंबे इंतजार को खत्म करने के बाद 'आर्सेनल' भी 5 नामित टीम में शामिल है। 'गनर्स' ने 22 साल बाद इंग्लिश चैंपियनशिप जीती और यूरोप में भी आगे बढ़कर एक मजबूत कैंपेन पूरा किया।
जर्मनी में एक और शानदार सीजन के बाद 'बायर्न म्यूनिख' शॉर्टलिस्ट में शामिल हुआ है। इस बड़े क्लब ने बुंडेसलीगा, जर्मन कप और जर्मन सुपर कप जीते, जिससे घरेलू स्तर पर उनका दबदबा साबित हुआ।

बेन शेल्टन ने किया बड़ा उलटफेर

यूएस ओपन: क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अल्काराज को हराया

नई दिल्ली। बेन शेल्टन ने बुधवार को यूएस ओपन 2026 में बड़ा उलटफेर किया। रोमांच से भरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में शेल्टन ने मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्काराज को 6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6, 7-6(10/7) से हराकर टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखाया। शेल्टन ने चार घंटे 28 मिनट तक चले इस मुकाबले में अपने करियर की सबसे बड़ी जीत के साथ ही मेजर टूर्नामेंट्स में स्पेनिश खिलाड़ी की लगातार 18 जीत का सिलसिला भी तोड़ दिया। यह मैच यूएस ओपन के इतिहास का सबसे देर तक चलने वाला मुकाबला रहा। मैच के आखिर में बेन शेल्टन ने 146 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ऐस सर्विस लगाकर अपनी जीत पक्की की। इससे पहले सबसे देर से खत्म होने वाले मैच का रिकॉर्ड कार्लोस अल्काराज के नाम था। दो साल पहले उन्होंने क्वार्टर फाइनल में यानिक सिनर को पांच सेटों के रोमांचक मुकाबले में हराया था। मॉन्ट्रियल में अपना दूसरा एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले बेन शेल्टन ने अल्काराज को हराकर पहली बार हार्ड कोर्ट मेजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाई है।

कार्लोस अल्काराज चोट के कारण करीब चार महीने बाद किसी बड़े टूर्नामेंट में खेल रहे थे। इसके बावजूद उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने के दौरान सिर्फ एक सेट गंवाया था। हालांकि, बेन शेल्टन ने उनका खिताब का बचाव करने का अभियान रोक दिया।

अल्काराज इस बार अपना आठवां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने और यूएस ओपन का खिताब लगातार दूसरी बार जीतने की कोशिश कर रहे थे। अगर वह ऐसा कर लेते, तो रोजर फेडरर के बाद यूएस ओपन ट्रॉफी सफलतापूर्वक बचाने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन जाते। यह स्पेनिश खिलाड़ी अपना आठवां मेजर खिताब जीतने और रोजर फेडरर के बाद यूएस ओपन का खिताब बचाने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बनने की कोशिश कर रहा था।

अल्काराज मेजर टूर्नामेंट्स में लगातार 18 जीत के सिलसिले के साथ क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उतरे थे। यह उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, जिसमें 2025 यूएस ओपन की जीत और इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीतना शामिल था। ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर वे करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले सबसे युवा पुरुष खिलाड़ी बने थे। शेल्टन अब सेमीफाइनल में 11वीं वरीयता प्राप्त फ्रांसिस टियाफो का सामना करेंगे। दोनों खिलाड़ी अपने पहले मेजर फाइनल में पहुंचने की कोशिश करेंगे। टियाफो के साथ मुकाबलों में शेल्टन 3-1 से आगे हैं। दोनों के बीच अब तक चार मुकाबले हुए हैं, जिनमें से दो यूएस ओपन के हार्ड कोर्ट पर खेले गए हैं। 2023 में क्वार्टर फाइनल मुकाबला शेल्टन ने जीता था, जबकि 2024 में तीसरे दौर के मुकाबले में टियाफो ने जीत दर्ज की थी।

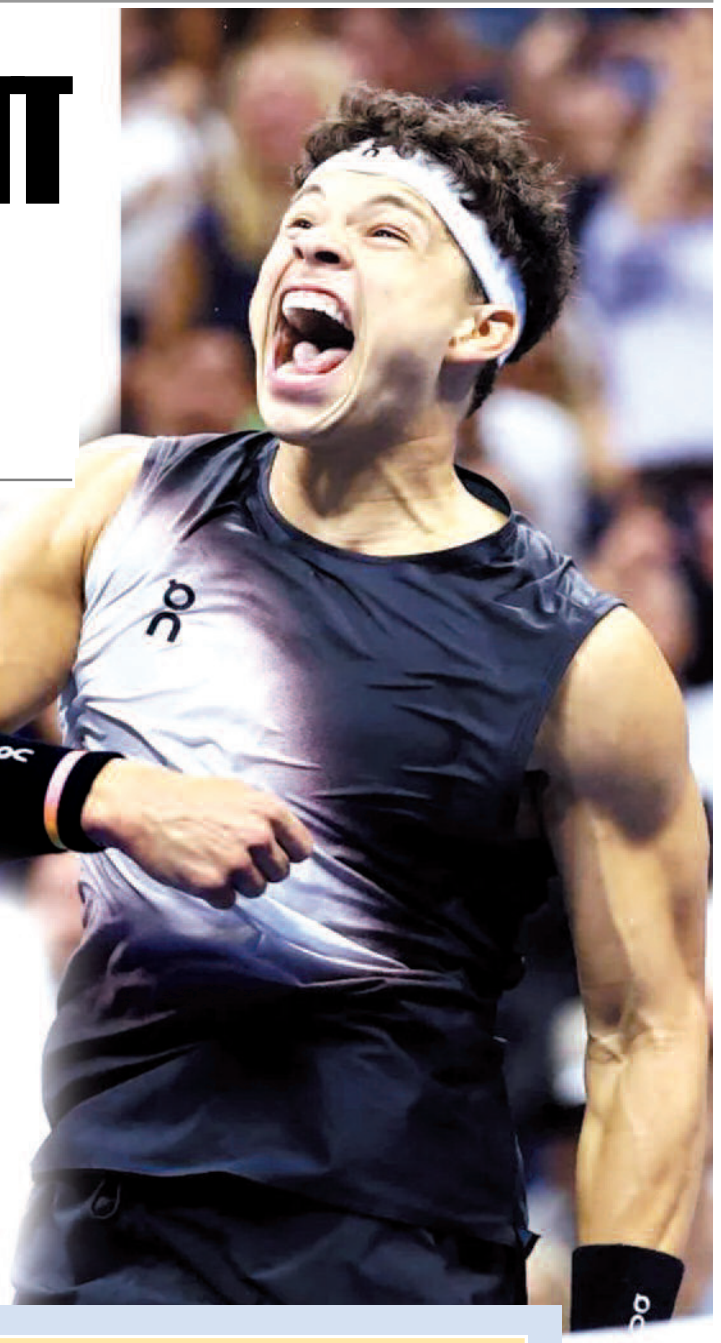

फ्रांसेस टियाफो सेमीफाइनल में, शुरुआत 2 सेट में हार के बाद एलेक्स मिशेलसन को हराया

न्यूयॉर्क। अमेरिका के फ्रांसेस टियाफो ने हमवतन एलेक्स मिशेलसन को हराकर यूएस ओपन 2026 के एकल वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। टियाफो ने दो सेट गंवाने के बाद यादगार वापसी करते हुए मुकाबला अपने नाम किया और अंतिम चार में जगह सुनिश्चित की। टियाफो तीसरी बार सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। ग्यारहवीं सीड टियाफो को शुरुआत के दो सेट में दुनिया के 46वें नंबर के खिलाड़ी मिशेलसन ने हराया। टियाफो तीसरे सेट में भी 5-3 से पिछड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि टियाफो मौजूदा टूर्नामेंट का अपना करिश्मा खो रहे हैं, लेकिन उसी समय उन्होंने वापसी की। उन्होंने न सिर्फ तीसरा सेट जीता, बल्कि मुकाबला भी अपने नाम किया।

टियाफो ने 10-पॉइंट के टाई-ब्रेक में जीत हासिल की और 4 घंटे 38 मिनट तक चले मुकाबले को 5-7 3-6 7-5 6-3 7-6 (10-6) से अपने नाम किया। इस दौरान टियाफो को भीड़ का जोरदार समर्थन मिला। 22 साल के मिशेलसन अपना पहला क्वार्टर फाइनल खेल रहे थे। विजयी शुरुआत के बाद मिली हार ने उन्हें बेहद निराश कर दिया था। मैच समाप्ति के बाद मिशेलसन अपने आंसू नहीं रोक सके और टियाफो के गले लगकर रोने लगे। टियाफो ने कहा, 'वह बहुत अच्छा खिलाड़ी है। वह आसानी से जीत सकता था। एलेक्स मिशेलसन को सलाम।' सेमीफाइनल में जगह बनाने के बाद टियाफो ने पहली बार फाइनल में पहुंचने की उम्मीद जताई।

फाईव स्टार होटल में नहीं रुकेंगे भारतीय क्रिकेटर

BCCI बोला- खिलाड़ी व्यवस्था से संतुष्ट

नई दिल्ली। जापान में होने वाले आगामी एशियाई खेलों में हिस्सा लेने वाले भारतीय क्रिकेटर आयोजन समिति की ओर से तय आवास में ही ठहरेंगे। क्रिकेटरों को विदेशी दौरों पर आमतौर पर मिलने वाले पांच सितारा होटलों जैसी सुविधाएं नहीं मिलेगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने मंगलवार (8 सितंबर) को यह जानकारी दी। शुक्ला ने कहा कि नागोया में शीर्ष श्रेणी के होटलों की कमी के कारण क्रिकेटरों के ठहरने को लेकर सवाल उठे थे, लेकिन आवास को लेकर कोई बड़ी समस्या नहीं है और बीसीसीआई तथा खिलाड़ी मौजूदा व्यवस्था से संतुष्ट हैं।

भारतीय दल के विदाई समारोह के दौरान शुक्ला ने कहा, 'आयोजक जो सुविधा दे रहे हैं, हम वहीं ठहर रहे हैं। हम लगातार यह देख रहे हैं कि खिलाड़ियों को किस तरह का आवास दिया जा रहा है, ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो। निश्चित तौर पर यह पांच सितारा नहीं है लेकिन अच्छा और आरामदायक आवास है। क्रिकेटरों के लिए जो आवास तय किये गये हैं, उसकी तस्वीरें और वीडियो हमने मंगवाए हैं। मुझे लगता है कि यह आरामदायक है।

आवास से जुड़ी समस्या हल हो गई: पीटी उषा

भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की अध्यक्ष पीटी उषा ने भी कहा कि आवास से जुड़ी समस्या का समाधान कर लिया गया है। उषा ने कहा, 'कोई समस्या नहीं है। हमने होटल पहले ही बुक कर लिए हैं। हम हर खिलाड़ी के लिए अलग से होटल का कमरा बुक नहीं कर सकते, क्योंकि वहां खिलाड़ियों के गांव जैसी व्यवस्था नहीं है। आयोजक जहाज और छोटे विला जैसी आवास सुविधाएं भी उपलब्ध करा रहे हैं।'

क्रिकेटरों के आवास की व्यवस्था किसने की-
क्रिकेटरों के आवास की व्यवस्था किसने की यह पूछे जाने पर शुक्ला ने कहा, 'इसकी व्यवस्था भारतीय ओलंपिक संघ, एशियाई खेल आयोजन समिति और जापान क्रिकेट संघ मिलकर कर रहे हैं।' उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम की तैयारियों के बारे में पूछे जाने पर कहा, 'भारत निश्चित तौर पर वहां अच्छा प्रदर्शन करेगा। भारतीय टीम 22 सितंबर को पहली बार जापान के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच (सुजुकी कप) खेलेगी। यह जापान में होने वाला पहला मैच होगा।
एसीसी व्यवस्थाओं से संतुष्ट- शुक्ला ने आवास के मुद्दे को ज्यादा तवज्जो नहीं देते हुए कहा कि असली चिंता मैदान, पिच और ड्रेसिंग रूम की स्थिति को लेकर थी। उन्होंने बताया कि एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) की टीम नागोया का दौरा कर चुकी है और वहां की व्यवस्थाओं से संतुष्ट है।

महिला एशिया कप: यूएई को हरा सेमीफाइनल में पहुंचा बांग्लादेश

भारत से मुकाबला आज

नई दिल्ली। महिला एशिया कप 2026 के 12वें मैच में मंगलवार (8 सितंबर) को बांग्लादेश ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को 34 रनों से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। पहले सेमीफाइनल में गुरुवार (10 सितंबर) को उसका सामना भारत से होगा। दूसरा सेमीफाइनल पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच 11 सितंबर को होगा। दोनों सेमीफाइनल के विजेताओं के बीच रविवार (13 सितंबर) को खेला जाएगा। ग्रुप ए में भारत पहले और पाकिस्तान दूसरे नंबर पर रहा। ग्रुप बी में श्रीलंका पहले और बांग्लादेश दूसरे नंबर पर रहा। यूएई ने टॉस जीतकर बांग्लादेश के खिलाफ गेंदबाजी का फैसला किया। बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 103 रन ही बना पाई। शर्मिन अख्तर ने 31 गेंद पर 38 रनों की पारीखेली। कप्तान निगार सुल्ताना ने 28 गेंद पर 23 रन बनाए। जुआरिया फिरदौस ने और नाहिदा अख्तर ने 16-16 रन बनाए।

यूएई 69 पर आउट

यूएई के लिए सुरक्षा कोटे ने 3 विकेट लिए। इंधुजा नंदकुमार ने 2 विकेट लिए अचार्य सुप्रिया और जननी थिरुककुमारन ने 1-1 विकेट लिए। यूएई की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 69 रन ही बना पाई। हीना होतचंदानी ने सबसे ज्यादा 18 रन बनाए। तीर्थ सतीश ने 11 रन बनाए।

राबेया खान ने 3 विकेट लिए

मेहुल प्रणव कुलकर्णी ने नाबद 9, समायरा धरनीधरका ने 8, जननी थिरुककुमारन ने 6, रिनिथा रजिथ ने 5, इंधुजा नंदकुमार ने 3, ईशा ओजा ने 2 और सुरक्षा कोटे ने 1 रन बनाए। बांग्लादेश के लिए राबेया खान ने 3, नाहिदा अख्तर और मरुफा अख्तर ने 2-2 विकेट लिए। सुल्ताना खातून और फहिमा खातून ने 1-1 विकेट लिए।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संक्षिप्त समाचार

टीवी एंकर चेंग लेई ने तीन साल जेल में गुजारा अमानवीय जीवन, अब पूरी दुनिया को कर रहीं आगाह

सिडनी, एजेंसी। चीन दुनियाभर में अपनी सौम्य और अच्छी छवि दिखाने की कोशिश करता है लेकिन लोगों को उसके दिखावटी चेहरे पर भरोसा करने के बजाय हकीकत की गहराई से पड़ताल करनी चाहिए। चीन ऐसा देश है जो अपने नागरिकों और विदेश में रहने वाले प्रवासियों को दुश्मन के तौर पर देखता है। यह कहना है चीनी-ऑस्ट्रेलियाई एंकर चेंग लेई का, जिन्हें महज एक मैसेज भेजने के कारण तीन साल चीन की जेल में बिताने पड़े थे। चीन में जन्मीं और ऑस्ट्रेलिया में पली बढ़ी चेंग लेई को बिना किसी ठोस कारण 1,154 दिन तक जेल में अमानवीय यातनाएं सहनी पड़े। चेंग लेई को अक्तूबर 2023 में चीन की जेल से रिहा किया गया था और अब वह ऑस्ट्रेलिया में बतौर एंकर काम कर रही हैं। लेकिन जेल से बाहर आने का मतलब यह नहीं है कि उनका संघर्ष खत्म हो गया है। उनका मानना है कि कैद का असर उनके जीवन पर हमेशा रहेगा और एक तरह से यह सजा रिहाई के बाद भी जारी है। तमाम मानसिक आघातों के बावजूद, लेई अब स्कूबा डाइविंग, कॉमेडी और थिएटर के जरिये जिंदगी को सामान्य बनाने की कोशिश कर रही हैं। जेल में बताए अपने अनुभवों के आधार पर वह चीन की सच्चाई पर पूरी दुनिया को आगाह कर रही हैं।

भारत-बांग्लादेश में जल्द बहाल होंगी ट्रेन सेवाएं: मैत्री, बंधन-मिताली एक्सप्रेस पर आज मंथन; नया रूट भी संभव

ढाका, एजेंसी। भारत और बांग्लादेश के बीच इस सप्ताह यात्री ट्रेन सेवाओं को फिर शुरू करने पर बातचीत होने जा रही, जो 2024 में शेख हसीना सरकार के पतन के दौरान हुई हिंसक अशांति के बाद से बंद पड़ी हैं। बांग्लादेश रेलवे के अधिकारी मंगलवार से ढाका में भारतीय समकक्षों के साथ दो दिवसीय इंटर-गवर्नमेंटल रेलवे मीटिंग (आईजीआरएम) करेंगे। इसमें मैत्री, बंधन और मिताली एक्सप्रेस को दोबारा शुरू करने के साथ ही एक नए रूट पर भी चर्चा होगी। मैत्री एक्सप्रेस ढाका को कोलकाता से, बंधन एक्सप्रेस खुलना को कोलकाता से और मिताली एक्सप्रेस पहले ढाका को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ती थी। बांग्लादेश की ओर से राजशाही को कोलकाता से जोड़ने वाला नया रूट प्रस्तावित किए जाने की संभावना है। साथ ही मैत्री एक्सप्रेस को जमुना पुल के बजाय नवनिर्मित पद्मा पुल से चलाने का भी प्रस्ताव आ सकता है। अधिकारी के अनुसार दोनों पक्षों की सहमति बनी तो अगले महीने से सेवाएं फिर शुरू हो सकती हैं। हालांकि, अंतिम फैसला दोनों देशों के राजनीतिक नेतृत्व को लेना होगा।

लेबनान में इस्राइली हमले में 12 की मौत: हूती लड़ाकों का दावा- सऊदी विमान गिराया; प. एशिया में क्या हैं हालात

दुबई, एजेंसी। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि दक्षिणी इलाके के एक गांव पर इस्राइली हवाई हमलों में 12 लोगों की मौत हुई है। इनमें दो बच्चे भी शामिल हैं।इस बीच, ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के एक टोही विमान को मार गिराने का दावा किया है। पिछले हफ्ते सऊदी अरब के एक टैंकर पर हमला हुआ था। उसके चालक दल के सात सदस्य अब भी लापता बताए जा रहे हैं। इस्राइल ने सोमवार तड़के दक्षिणी लेबनान के कफर रुमान गांव पर हवाई हमले किए। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, हमले में कम से कम 12 लोगों की मौत हुई। इनमें एक पैरामेडिक, चार महिलाएं और दो बच्चे शामिल हैं। यह हमला इस्राइल और ईरान समर्थित हिजबुल्ला के बीच बढ़े तनाव के बीच हुआ। इस्राइली सेना ने कहा कि उसने हिजबुल्ला के कई लड़ाकों को निशाना बनाया। सेना के अनुसार, ये लोग कफर रुमान में हथियार पहुंचा रहे थे। सेना ने यह भी कहा कि वह इस दावे की जांच कर रही है कि रात के हमलों में कई आम लोग घायल हुए। इस्राइल के अनुसार, ये हमले हिजबुल्ला के उन लड़ाकों के जवाब में किए गए, जिन्होंने इलाके में सैनिकों पर विस्फोटक ड्रोन से हमला किया था। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सोमवार को दावा किया कि उन्होंने उत्तरी यमन में सऊदी अरब का एक सशस्त्र टोही विमान मार गिराया। हूती सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सरी ने यह दावा किया। उन्होंने कहा कि विमान जौफ प्रांत के हवाई क्षेत्र में देखा गया था। उनके अनुसार, यह सऊदी अरब का विमान था और कथित तौर पर 'दुश्मनी की कार्रवाई' के लिए वहां आया था। इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। सऊदी अरब की ओर से भी तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। हूती प्रवक्ता ने कहा कि पिछले 24 घंटे में सऊदी अरब के कुल तीन टोही ड्रोन मार गिराए गए हैं। इनमें से एक सोमवार सुबह बायदा प्रांत में देखा गया था।

समुद्र में अमेरिका का कहर: इक्वाडोर का पांचवां जहाज डुबोया, 227 मौतों ने बढ़ाई चिंता

क्विटो, एजेंसी। अमेरिकी दक्षिणी कमान ने सोमवार को प्रशांत महासागर में इक्वाडोर के एक जहाज को डुबो दिया। अमेरिका का आरोप है कि यह जहाज अपराधी संगठन लॉस चोनेरोस से जुड़ा था। अमेरिकी कमान के मुताबिक, यह एक तैरता हुआ ईंधन केंद्र था। इसका इस्तेमाल समुद्र में नशीली दवाओं की तस्करी के अभियानों को मदद देने के लिए किया जा रहा था। कार्रवाई पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में हुई। जहाज पर मौजूद लोगों को पहले उतार लिया गया। अब उन्हें इक्वाडोर के अधिकारियों को सौंपा जाएगा।

अमेरिका ने कार्रवाई का वीडियो भी जारी किया : अमेरिकी दक्षिणी कमान ने कार्रवाई से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया। इसमें अमेरिकी सैन्यकर्मी एक जहाज पर चढ़ते दिख रहे हैं। इसके बाद ऊपर से एक हेलीकॉप्टर उड़ता नजर आता है। आखिर में एक प्रक्षेपास्त्र जहाज से टकराता है और वह समुद्र में डूब जाता है। अमेरिकी कमान ने कहा कि उसकी सेनाएं पश्चिमी गोलार्ध में नशीली दवाओं की तस्करी को बढ़ावा देने वाले लॉजिस्टिक नेटवर्क को खत्म करने के लिए सटीक और पेशेवर अभियान जारी रखे हुए हैं।

क्या पहली बार हुई ऐसी कार्रवाई : नहीं। यह दो हफ्ते से भी कम समय में अमेरिकी सेनाओं का पांचवां निशाना है। इससे पहले प्रशांत महासागर में मछली पकड़ने वाले जहाज मारिया कैंडेलारिया को निशाना बनाया गया था। इक्वाडोर की नौसेना ने इस जहाज के 26 सदस्यों को खोज लिया। वे रविवार को बंदरगाह शहर मांटा पहुंचे। कॉन्क्विस्टा-2 के आठ मछुआरे भी मिल गए हैं। हालांकि, उनके परिवार देश की मुख्य भूमि पर उनकी जानकारी को लेकर चिंता जताते रहे।

मामले से जुड़ी बड़ी बातें : मारिया कैंडेलारिया: पिछले सप्ताह प्रशांत महासागर में इस जहाज को निशाना बनाया गया था। इक्वाडोर की नौसेना ने बाद में इसके 26 सदस्यों को खोज लिया।

कॉन्क्विस्टा-2: इस जहाज के आठ मछुआरे भी मिल गए हैं। उनके परिवार उनके ठिकाने की जानकारी मांग रहे थे।

ओएम-2 और लॉस ट्रेस हरमानोस: इन दोनों जहाजों के चालक दल का कहना है कि अमेरिकी कार्रवाई में उनके जहाज डुबो दिए गए।

तैरते ईंधन केंद्र: अमेरिकी कमान ने ओएम-2 और लॉस ट्रेस हरमानोस को कई जहाजों को अवैध ड्रग तस्करी में मदद देने वाले तैरते ईंधन केंद्र बताया है।

लॉस चोनेरोस कनेक्शन: अमेरिका का कहना है कि निशाना बनाए गए सभी जहाज लॉस चोनेरोस से जुड़े थे। अमेरिका इस संगठन को विदेशी आतंकवादी संगठन मानता है।

पुराने मामलों का विवाद: इस साल तीन अन्य जहाजों के इक्वाडोरियन चालक दल भी अमेरिकी सेनाओं द्वारा रोके जाने की बात कह चुके हैं। इनमें फियोरेला भी शामिल है, जिसके आठ मछुआरे जनवरी से लापता हैं। मौतों का आंकड़ा: एक साल से ज्यादा समय में कैरेबियन और प्रशांत क्षेत्र में नावों के खिलाफ अमेरिकी सरकार की 68 कार्रवाइयों में कम से कम 227 लोग मारे गए हैं। इन हमलों की वैधता और प्रभावशीलता पर सवाल उठे हैं।

क्या अमेरिका के दावे पर भी उठे सवाल : इन समुद्री हमलों की कानूनी वैधता और उनकी प्रभावशीलता पर आलोचक सवाल उठा रहे हैं। कम से कम एक मामले में इक्वाडोर के अधिकारियों ने कहा था कि हमले में बचे एक व्यक्ति के किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल होने का उनके पास कोई सबूत नहीं था। इस बीच, इक्वाडोर के अधिकारियों ने नए डूबे जहाज की कार्रवाई पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। जहाज का नाम भी सार्वजनिक नहीं किया गया है।

जमीन पर भी ऐसी कार्रवाई करने की तैयारी में अमेरिका : ट्रंप प्रशासन सहयोगी देशों के साथ ऐसे समझौते करने की कोशिश कर रहा है, जिससे अभियान को कई लैटिन अमेरिकी देशों की जमीन तक बढ़ाया जा सके। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने इस महीने पनामा यात्रा के दौरान कहा था कि कोलंबिया, ग्वाटेमाला और होंडुरास ने अपनी जमीन पर आपराधिक समूहों के खिलाफ संयुक्त अमेरिकी सैन्य अभियान की अनुमति देने पर सहमति जताई है। हालांकि, ग्वाटेमाला ने ऐसा कोई समझौता होने से इनकार किया है। इक्वाडोर ने मार्च में अमेरिका के साथ इसी तरह के संयुक्त अभियान शुरू किए थे।

अमेरिका में करना होगा उत्पादन': ट्रंप की कनाडा की विमान कंपनी को चेतावनी; ओटावा पर क्यों भड़का ईरान

वाशिंगटन/तेहरान, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा की विमान कंपनी बॉम्बार्डियर को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि अगर कंपनी अपने विमान बेचना चाहती है, तो उसे अपना उत्पादन अमेरिका में शुरू करना होगा। ट्रंप ने सोमवार को सोशल मीडिया पर लिखा, अमेरिका में बॉम्बार्डियर की बिक्री अब और नहीं। उनके उत्पाद इतने अच्छे नहीं हैं। उन्होंने कहा, उनकी (कनाडा) 50 फीसदी से ज्यादा कमाई अमेरिका से होती है। वे अमेरिकी खरीदारों, अमेरिकी कंपनियों, हवाई अड्डों और सेवाओं पर निर्भर हैं। वहीं, कनाडा पूरे अमेरिका में हमारे महान अमेरिकी बैंकों और कंपनियों को रोकता है।

ट्रंप ने अमेरिकी विमान कंपनी गल्फस्ट्रीम एयरोस्पेस का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कनाडा ने इस कंपनी को अपने बाजार में कारोबार करने से गलत तरीके से रोका है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, उन्होंने गल्फस्ट्रीम एयरोस्पेस को भी कनाडा में कारोबार करने से रोक दिया। यह पूरी तरह गलत और अनुचित है। वह दौर अब खत्म हो गया। उन्होंने कहा, अगर उन्हें हमारा बाजार चाहिए, तो उन्हें यहां उत्पादन करना होगा। अमेरिका को 'पिगी बैंक' समझना बंद करना होगा। इसके बाद ट्रंप ने कहा, 'अमेरिकी सामान खरीदें। अमेरिकी विमानों से उड़ान भरें। अमेरिकी शराब और पेय का आनंद लें। लेक अमेरिका में नौकायन करें। अमेरिका पहले।' ट्रंप का यह बयान दोनों देशों के बीच चल रहे व्यापार विवाद के बीच आया है। अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापार वार्ता टूटने के बाद तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों ने एक-दूसरे के सामान पर जवाबी टैरिफ लगाने की धमकी भी दी है।

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि उनका देश अमेरिका के साथ ऐसा लंबे समय का व्यापार समझौता चाहता है, जिससे दोनों देशों को फायदा हो। उन्होंने कहा कि कनाडा अपने कर्मचारियों, परिवारों और कारोबार के हितों की रक्षा करता रहेगा। कार्नी ने कहा, हम हमेशा कनाडा, कनाडाई कर्मचारियों और कनाडाई परिवारों के हित में खड़े होंगे। हम किसी आसान जीत या सिर्फ घोषणा की तलाश में नहीं हैं। हम ऐसा समझौता चाहते हैं, जो लंबे समय तक चले। ऐसा समझौता संभव है और यह दोनों के हित में है। कार्नी ने कहा कि ऐसा समझौता कनाडा के कर्मचारियों, परिवारों और कारोबार के साथ-साथ अमेरिकी उपभोक्ताओं, कारोबार और परिवारों के लिए भी फायदेमंद होगा। उन्होंने कहा कि कनाडा अब सिर्फ अमेरिका के अगले कदम का इंतजार नहीं करेगा।

यमन में जेल पर सऊदी हमले का आरोप: बच्चे समेत सात की मौत; हूतियों का दावा- लेंगे बदला; तनाव क्यों बढ़ा

काहिरा, एजेंसी। यमन के उत्तरी हिस्से में सोमवार को एक जेल पर हमला हुआ। हूती विद्रोहियों ने आरोप लगाया कि यह हमला सऊदी अरब ने किया। हमले में कम से कम सात लोगों की मौत हुई। इनमें एक बच्चा भी शामिल है। कम से कम सात लोग घायल बताए गए हैं। घायलों में एक महिला भी है। हमला रणनीतिक रूप से अहम अल-जौफ प्रांत के हज्म शहर में स्थित सेंट्रल करेक्टिव फैसिलिटी पर हुआ। जेल की इमारत का एक हिस्सा हमले के बाद मलबे में बदल गया। जेल वार्डन के मुताबिक, 35 कैदी और पति से मिलने आई एक महिला मलबे में फंसे थे।

हूती स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता अनीस अल-असबही ने सऊदी अरब पर हमले का आरोप लगाया। हूती सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने भी सऊदी अरब पर हवाई हमले करने और जौफ में 'नरसंहार' करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ने एक निगरानी ड्रोन भी तैनात किया और भाड़े के लड़ाकों को अलग-अलग हथियार मुहैया कराए। सारी ने कहा, 'यमन के खिलाफ जारी सऊदी आक्रामकता का जवाब दिया जाएगा और उसे सजा मिलेगी।' सऊदी अरब के मीडिया मंत्रालय की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। नहीं। यमन युद्ध के दौरान जेलों और हिरासत केंद्रों पर पहले भी हमले हुए हैं। 2022 में सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के एक हमले में उत्तरी सादा प्रांत की एक हिरासत सुविधा निशाना बनी थी। इसमें कम से कम 87 कैदियों की मौत हुई थी और करीब 266 लोग घायल हुए थे। सितंबर 2019 में दक्षिण-पश्चिमी धमर प्रांत में हूतियों द्वारा संचालित हिरासत केंद्र पर हमला हुआ था। इसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और दर्जनों घायल हुए थे। यमन में गृहयुद्ध 2014 में शुरू हुआ। तब हूती विद्रोही अपने उत्तरी गढ़ से आगे बढ़े और राजधानी सना पर कब्जा कर लिया। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार को पहले दक्षिण और फिर सऊदी अरब में निर्वासन के लिए जाना पड़ा। सरकार को बहाल करने के लिए अगले साल सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने युद्ध में दखल दिया।

9/11 के 25 साल बाद खुली पुरानी फाइल: अल-कायदा नेता संग दिखा संदिग्ध, एफबीआई ने क्यों नहीं की कार्रवाई

इस्लामाबाद, एजेंसी। 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमलों के करीब 25 साल बाद ओमर अल-बायूमी को लेकर नए सवाल खड़े हुए हैं। बीबीसी की रिपोर्ट में ऐसे पुरानी वीडियो फुटेज सामने आए हैं, जिनमें बायूमी भविष्य के अल-कायदा नेता अनवर अल-अवलाकी के साथ नजर आ रहा है। एक फुटेज में दोनों सैन डिएगो के पास पेंटबॉल खेलते दिखते हैं। दूसरे वीडियो में बायूमी और अवलाकी एक-दूसरे को गले लगाते नजर आते हैं। खास बात यह है कि इन फुटेज को एफबीआई ने 9/11 हमलों के कुछ ही दिनों बाद हासिल कर लिया था।

पेंटबॉल वाले वीडियो में क्या दिखा : बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, 1997 या 1998 की शुरुआत में बनाए गए वीडियो में बायूमी, अवलाकी और दूसरे लोग सैन्य अंदाज में पेंटबॉल खेलते दिखते हैं। कुछ प्रतिभागियों ने सैन्य वर्दी जैसे कपड़े पहन रखे थे। लड़ाई के दौरान कुछ लोग 'अल्लाहु अकबर' भी चिल्लाते सुनाई देते हैं। एफबीआई अधिकारियों को जांच के दौरान बताया गया था कि इन पेंटबॉल सत्रों का इस्तेमाल कुछ लोग जिहाद की ट्रेनिंग के लिए करते थे। इसी फुटेज में सऊदी अरब के इस्लामिक अफेयर्स मंत्रालय से जुड़े एक अधिकारी की मौजूदगी भी बताई गई है। बायूमी और अवलाकी की नजदीकी वीडियो में साफ दिखाई देती है। फुटेज में सैन्य अंदाज वाले पेंटबॉल मुकाबले दर्ज हैं। कुछ लोगों के जिहाद प्रशिक्षण से जुड़े होने की बात एफबीआई तक पहुंची थी। बायूमी के सऊदी अधिकारियों से संपर्क भी सामने आया था।

बायूमी के पास ऐसा कौन सा सबूत मिला था, जिसने एफबीआई को चौंकाया : 21 सितंबर 2001 को ब्रिटेन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने बायूमी को गिरफ्तार किया था। तलाशी में हजारों दस्तावेज, तस्वीरें और कम से कम 80 वीडियो टेप मिले। इनमें एक नोटबुक का पन्ना खास था। उस पर एक विमान का चित्र बना था। साथ ही विमान की ऊंचाई और किसी लक्ष्य से उसकी दूरी से जुड़ी गणनाएं भी थीं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, 9/11 पीड़ित परिवारों की कानूनी टीम ने इसे बेहद अहम सबूत माना। टीम की सदस्य जोडी वेस्टब्रुक फ्लावर्स ने कहा, 'जब हमें पता चला कि यह क्या था, तो हमें लगा कि हमें उस सबूत का सबसे अहम टुकड़ा मिल गया है, जिसकी तलाश थी।' बाद में एक संघीय जज ने कहा कि यह दस्तावेज अपने चेहरे पर ही बायूमी को 9/11 हमलों की जानकारी से जोड़ता है। यही इस मामले का सबसे बड़ा सवाल है।

नेपाल जलप्रलय: 65 स्कूल कल से खुलेंगे, बच्चों को सदमे से निकालने की कोशिश; देश में 13वें दिन शोक

काठमांडू, एजेंसी। नेपाल में जल प्रलय के दो हफ्ते पूरे होने वाले हैं लेकिन नुवाकोट, रसुवा और आसपास के जिलों में जिन बच्चों ने बाढ़ का तांडव देखा या अपनों को खोया, वे एक अदृश्य डर से जूझ रहे हैं। कोई आधी रात को चौंककर उठ जाता है, कोई गुमसुम हो जाता है, तो कोई आपदा की याद दिलाने वाली किसी भी आवाज से सहम जाता है।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को फिर से बसाने की कवायद के बीच इन बच्चों को सदमें से बाहर लाने की कोशिशें भी जारी हैं। मेडिकल टीमें मानसिक सेहत सुधारने के लिए काउंसलिंग भी करा रही है। नुवाकोट के बिधुर में प्रशासन बुधवार से 65 स्कूलों को खोलने की तैयारी भी कर रहा है। बाढ़ से पहले बिदुर में कुल 79 स्कूल चल रहे थे। बिदुर की डिप्टी मेयर प्रभा बोगटी ने कहा, स्कूल इस बात का बंदोबस्त करेंगे कि वे आसानी से अपनी कक्षाओं में शामिल हो सकें। इस बीच, आपदा के 13वें दिन नेपाल में राष्ट्रीय शोक मनाया गया। इस दौरान राष्ट्र ध्वज को आधा झुका दिया गया और दीये और मोमबत्तियां जलाकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। एजेंसी 2023 में भारत में सुरंग से 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाने वाले ऑस्ट्रेलियाई सुरंग विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिक्स चिलिमे जलविद्युत परियोजना की सुरंग में फंसे लोगों की तलाश में जुटे हैं। उन्होंने कहा, नेपाल का अभियान सिलक्यारा से अधिक चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि यहां एक साथ कई स्थानों पर बचाव कार्य चल रहा है। महराजगंज, कुशीनगर समेत कई सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ जैसे हालात के कारणमादा क्यूलेक्स मच्छर के पनपने और अंडों को सुरक्षित रखने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। नेपाल आपदा ने भारत के पूर्वी सीमांत क्षेत्रों में जापानी इंसेफेलाइटिस के लिए जमीन तैयार कर दी है। अगर निवारक उपायों की दिशा में मजबूत कदम नहीं उठाए गए तो लोगों को दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आपदा से महराजगंज और कुशीनगर समेत कई इलाकों में महीनों दल-दल बने रहने की संभावना है। प्रभावित क्षेत्रों में अब हाईग्रेड फीवर के मरीज भी लगातार बढ़ रहे हैं जिसे जापानी इंसेफेलाइटिस का संकेत माना जाता है। ऐसे में ग्रामीणों ने गहरी चिंता जताई है। महराजगंज के सेहगीबर्वा निवासी रामधारी निशाद, कुशीनगर के तमकोही राज निवासी लोकेश और पीपरी घाट निवासी उज्वल सिंह कहते हैं बाढ़ का दूषित पानी गांव के किनारे तक पानी पहुंच गया है।

ईरान से युद्ध जीतते ही तेल होगा सस्ता': ट्रंप बोले- दो डॉलर से कम होगी गैस; एर्दोगन ने इस्राइल को कैसे घेरा

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका की जीत के बाद तेल की कीमतों में तेज गिरावट आएगी। ट्रंप ने सोमवार को अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर लिखा कि युद्ध जीतने के बाद तेल की कीमतें तेजी से गिरेंगी। उन्होंने कहा कि गैस की कीमत पहले तीन डॉलर प्रति गैलन तक आ सकती है और अंततः दो डॉलर प्रति गैलन से भी नीचे जा सकती है। ट्रंप ने यह भी दोहराया कि अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने अमेरिका को ईरान की ऊर्जा सुविधाओं पर किसी भी कार्रवाई के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ईरान का तेल और गैस उत्पादन तंत्र काफी फैला हुआ है और उसकी सुरक्षा आसान नहीं है। गालिबाफ ने कहा, 'हमारी संपत्तियों पर हमला करेंगे तो आप पर भी हमला होगा। हम यह पहले ही साबित कर चुके हैं। उन ठिकानों से पूछिए, जो अब काम करने लायक नहीं बचे।' यह बयान ऐसे समय आया है, जब अमेरिकी अधिकारियों की ओर से ईरान के तेल टैंकरों को निशाना बनाने की धमकी दी जा रही है।

अमेरिका ने ईरान के तेल टैंकरों को लेकर क्या कहा : अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेगसेथ ने कहा कि अगर ईरान अमेरिकी जहाजों पर हमला करता है तो अमेरिका उसके तेल टैंकरों को नष्ट कर देगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के पास न नौसेना बची है और न वायुसेना। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने तीन ईरानी कच्चे तेल के टैंकरों पर हमले का वीडियो भी साझा किया। कमांड के मुताबिक, ये टैंकर अरबों डॉलर के उस नेटवर्क का हिस्सा थे, जिससे ईरान का रिवोल्यूशनरी गार्ड और उसके क्षेत्रीय सहयोगी आर्थिक मदद हासिल करते हैं। सेंटकॉम कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा कि अमेरिकी जहाजों पर हमला हुआ तो ईरान की तेल आपूर्ति पर और बड़ी आर्थिक कीमत थोपी जाएगी।

दूसरी ओर, तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन ने इस्राइल पर मध्य पूर्व में संघर्ष भड़काने और शांति प्रयासों को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस्राइल की कार्रवाई के कारण जून में ईरान और अमेरिका के बीच हुआ 14 सूत्री इस्लामाबाद समझौता पटरी से उतर गया। एर्दोगन ने कहा कि इस युद्ध की कीमत सिर्फ ईरान और खाड़ी देशों को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को चुकानी पड़ रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक शांति को खतरे के रूप में देखने वाली सोच नहीं बदलेगी, तब तक क्षेत्र में संकट खत्म नहीं होगा। समझौते में सैन्य कार्रवाई रोकने, होर्मुज जलडमरूमध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही, प्रतिबंधों में राहत और ईरान के लिए कम से कम 300 अरब डॉलर के अमेरिकी समर्थित आर्थिक विकास कार्यक्रम जैसे प्रावधान शामिल थे। इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान की सरकार का अंत करीब है। उन्होंने कहा कि ईरानी शासन कमजोर है और अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि इस्राइल खुद की रक्षा करने और अपने दुश्मनों पर हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने विरोधियों को चेतावनी दी।

एफिल टावर में महिला कर्मचारियों को हटाने पर विवाद: बीएपीएस ने जताया खेद, कहा- किसी को अंदर जाने से नहीं रोका

पेरिस, एजेंसी। एफिल टावर में महिला कर्मचारियों को हटाए जाने के विवाद के बीच बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था (बीएपीएस) ने आज सफाई देते हुए कहा है कि उसके प्रतिनिधिमंडल के दौरे के दौरान किसी को भी स्मारक में प्रवेश से नहीं रोका गया था। बीएपीएस ने कहा कि बड़े प्रतिनिधिमंडल को देखते हुए दौरा एफिल टावर की टीम के साथ समन्वय कर सुबह के शुरुआती समय में रखा गया था, ताकि दूसरे पर्यटकों को कम परेशानी हो। हालांकि, संगठन ने स्थिति से किसी को हुई तकलीफ के लिए दिल से माफी मांगी और आपसी सम्मान व सेवा के मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं, महिला कर्मचारियों को ड्यूटी से हटाने के आरोपों के बाद एफिल टावर के कर्मचारियों ने विरोध किया, प्रबंधन से माफी और जांच की मांग की तथा पेरिस के मेयर ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं।

बड़े प्रतिनिधिमंडल की वजह से खास व्यवस्था : बीएपीएस के मुताबिक, प्रतिनिधिमंडल की संख्या काफी ज्यादा थी। इसी वजह से एफिल टावर की टीम के साथ समन्वय करके यह दौरा आम लोगों के लिए स्मारक खुलने के समय के शुरुआती हिस्से में रखा गया था, ताकि दूसरे पर्यटकों को कम से कम परेशानी हो और उनकी आवाजाही प्रभावित न हो। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि उसकी जानकारी के अनुसार, दौरे के दौरान किसी भी समय किसी को एफिल टावर में जाने से नहीं रोका गया। हालांकि, उसने यह भी कहा कि अगर इस पूरी स्थिति से किसी को किसी तरह की परेशानी या तकलीफ हुई है तो वह उसके लिए दिल से माफी मांगता है।

महिला कर्मचारियों को हटाने के आरोप से शुरू हुआ विवाद : दरअसल, सोमवार को पेरिस का एफिल टावर कुछ समय के लिए बंद रहा। कर्मचारियों ने एक बैठक और विरोध प्रदर्शन किया था। यह विरोध शनिवार को हुए एक दौरे से जुड़ा था, जिसमें करीब 100 लोगों का हिंदू धार्मिक प्रतिनिधिमंडल एफिल टावर पहुंचा था।

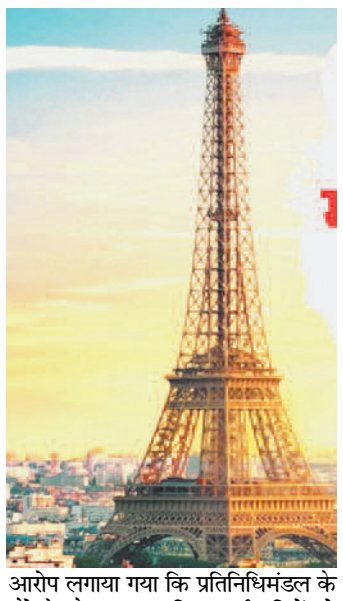

आरोप लगाया गया कि प्रतिनिधिमंडल के दौरे के दौरान कुछ महिला कर्मचारियों को उनकी काम की जगह से हटने के लिए कहा गया और उनकी जगह पुरुष कर्मचारियों को तैनात किया गया। इस घटना ने कर्मचारियों के बीच नाराजगी पैदा कर दी।

बीएपीएस से जुड़ा था प्रतिनिधिमंडल : शनिवार को एफिल टावर पहुंचा यह प्रतिनिधिमंडल बीएपीएस से जुड़ा हुआ था। यह समूह पेरिस के पास बने एक बड़े हिंदू मंदिर के उद्घाटन से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए फ्रांस आया था। यूनियन प्रतिनिधियों का कहना है कि प्रतिनिधिमंडल के गुजरने के दौरान महिला कर्मचारियों को अपनी ड्यूटी की जगह छोड़ने के लिए कहा गया। उनकी जगह पुरुष कर्मचारियों को तैनात किए जाने पर यूनियन ने सवाल उठाए और इसे लेकर कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ती गई। यूनियन प्रतिनिधि डायने डावोइन ने कहा कि इस घटना को लेकर कर्मचारियों का गुस्सा धीरे-धीरे बढ़ा और ऐसी स्थिति दोबारा नहीं होनी चाहिए, जिसमें महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाए।

कर्मचारियों की बैठक के बाद एफिल टावर खुलने में हुई देरी : सोमवार सुबह कर्मचारियों ने बैठक की। इसका उद्देश्य प्रबंधन के साथ इस मामले पर चर्चा करना और आगे ऐसी स्थिति न बनने की गारंटी हासिल करना था। कर्मचारियों की मांग थी कि भविष्य में किसी महिला कर्मचारी को केवल उसके जेंडर के आधार पर उसकी जिम्मेदारी या काम की जगह से पीछे न किया जाए। बैठक के चलते एफिल टावर को आम लोगों के लिए खोलने में देरी हुई। स्मारक पर एक नोटिस भी लगाया गया, जिसमें बताया गया कि संचालन संबंधी कारणों से एफिल टावर निर्धारित समय पर नहीं खुल पाएगा। यूनियन के मुताबिक, प्रबंधन ने इस घटना को लेकर कर्मचारियों से माफी मांगी है। हालांकि, कर्मचारियों का कहना है कि केवल माफी पर्याप्त नहीं है और पूरे मामले की विस्तृत जांच होनी चाहिए। एफिल टावर का संचालन करने वाली कंपनी सेटे ने भी विवाद पर प्रतिक्रिया दी। कंपनी ने माना कि प्रतिनिधिमंडल की ओर से महिला कर्मचारियों के साथ संपर्क कम रखने की मांग की गई थी। सेटे ने कहा कि इस तरह की शर्तों को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था।

स्वामी,मुद्रक व् प्रकाशक: सुरेश मौर्या द्वारा अष्ठ विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर,सिद्धिविनायक मंदीर के पास ,भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

झारखंड की वोटर लिस्ट में मिले अफगान के तीन नागरिक

रांची (एजेंसी)। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जमशेदपुर ईस्ट विधानसभा क्षेत्र की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में तीन अफगान नागरिकों के नाम पाए गए हैं, जिससे चुनाव अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया। दस्तावेजों की जांच के दौरान उनकी विदेशी पहचान सामने आने के बाद चुनाव अधिकारियों ने तुरंत मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक, आसिल खान, मोहम्मद असलम और मोहम्मद इब्राहिम नामक इन तीनों व्यक्तियों के नाम जमशेदपुर ईस्ट विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में दर्ज थे। इन तीनों ने गणना प्रक्रिया पूरी की थी और उनके नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में भी शामिल हो गए थे। हालांकि, दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान कुछ गड़बड़ी मिलने पर तीनों के नाम नोटिस लिस्ट में आए। चुनाव अधिकारियों की ओर से तीनों को नोटिस भेजकर जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा गया, लेकिन वे वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सके। इसके बाद उनके पासपोर्ट की गहन जांच की गई, जिसमें उनकी पहचान अफगान नागरिकों के तौर पर सामने आई। ये तीनों जमशेदपुर ईस्ट के पोलिंग स्टेशन नंबर 286 में क्रमशः 30, 31 और 33 नंबर पर दर्ज थे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने बताया कि तीन विदेशी नागरिकों की पहचान हुई है। इनमें से एक की विदेशी नागरिकता की पुष्टि हो चुकी है, जबकि दो अन्य संदिग्ध हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि तीनों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। रवि कुमार ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह भी पता लगाया जाएगा कि इन विदेशी नागरिकों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराने में किसने मदद की। उन्होंने इसे एक आपराधिक गतिविधि बताया और कहा कि इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक, इन तीनों के परिवार के अन्य सदस्यों की भी जांच की जाएगी और उनके दस्तावेजों का सत्यापन कर उनकी वास्तविक नागरिकता और स्थिति का पता लगाया जाएगा। मामले में जमशेदपुर के डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी को भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जांच पूरी होने के बाद संबंधित अधिकारियों की ओर से उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने यह भी कहा कि राज्य में ऐसे अन्य विदेशी नागरिकों की भी पहचान की जाएगी, जिनके नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो सकते हैं।

टेक्सटाइल मार्केट में लगी भीषण आग, 20 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर तैनात

सूरत (एजेंसी)। सूरत के सरोली इलाके में स्थित श्याम संगिनी टेक्सटाइल मार्केट में भीषण आग लग गई है। आग बुझाने करीब 20-22 दमकल गाड़ियां तैनात की गईं। बचाव अधिकारियों के मुताबिक फायर कंट्रोल रूम को पहली इमरजेंसी कॉल रात करीब 12:52 बजे मिली, जिसके बाद पास के तीन फायर स्टेशनों से तुरंत दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी गईं। इस घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं मिली है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सूरत नगर निगम के मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि आग से प्रभावित मंजिलों की काफी ऊंचाई के कारण टर्नटेबल लैडर और हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म की मदद से आग बुझाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दमकलकर्मी धुएं से भरे परिसर में घुसने और प्रभावित मंजिलों तक पहुंचकर आग पर काबू पाने के लिए ब्रीदिंग अपैरेटस सेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। आग की तीव्रता और दायरे को देखते हुए इसे मेजर फायर घोषित किया गया, जिसके बाद आग बुझाने और बचाव अभियान में मदद के लिए सूरत के अन्य इलाकों से अतिरिक्त दमकल गाड़ियां बुलाई गईं। सूरत नगर निगम के मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि आग से प्रभावित मंजिलों की काफी ऊंचाई के कारण टर्नटेबल लैडर और हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म की मदद से आग बुझाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल मार्केट में मंजिलें डबल-हाइट वाली हैं, जिसका मतलब है कि चौथी और पांचवीं मंजिलें असल में अपनी सामान्य ऊंचाई से कहीं ज्यादा ऊंचाई पर स्थित हैं। नतीजतन, दमकलकर्मियों को करीब 20 मीटर की ऊंचाई पर ऑपरेशन चलाना पड़ा।

गांव की लड़कियों से की शादी तो होगा बायकॉट, गुरुद्वारा सिंह सभा का फैसला

-गांव की लड़कियां शादी के लिए नहीं, बहन

जगराओं (एजेंसी)। पंजाब के रायकोट रोड स्थित रूबी गांव में प्रेम संबंधों को लेकर पंचायत और ग्रामीणों ने सख्त फैसला लिया है। गुरुद्वारा सिंह सभा में हुई बैठक में तय किया गया कि गांव का कोई युवक यदि गांव की ही लड़की को भगाकर ले जाता है या उससे शादी करता है, तो उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। युवक के परिवार के खिलाफ भी बहिष्कार की कार्रवाई की बात कही गई है। पंचायत ने यह भी कहा कि लड़की को भगाने के बाद युवक या उसके परिवार ने आत्महत्या की कोशिश की, तो पंचायत, ग्रामीण, समाजसेवी संस्थाएं और खेल क्लब उनकी मदद नहीं करेंगे। पंचायत के अनुसार, यह फैसला फिलहाल रूबी गांव तक सीमित है। आसपास के गांवों में भी जल्द महापंचायत बुलाकर ऐसे फैसलों पर विचार किया जाएगा। पंचायत ने गांव की लड़कियों को बहन मानने की अपील की है।

सत्य निकेतन इलाके में गिरी इमारत से सटी बिल्डिंग को गिराने की कार्रवाई शुरु

-हादसे में 7 लोगों की मौत हुई थी, पुलिस ने इस मामले में की चौथी गिरफ्तारी

नई दिल्ली, एजेंसी।
दिल्ली नगर निगम ने सत्य निकेतन इलाके में हादसे वाली इमारत से सटी बिल्डिंग को तोड़ना शुरू कर दिया है। 6 सितंबर को बिल्डिंग 'हॉस्टल डेज' ढहने के बाद अधिकारियों ने पड़ोस की इमारत को खतरनाक बताया था। मंगलवार को शुरू हुई कार्रवाई शाम तक चली, जो बुधवार सुबह फिर शुरू हो गई। इस बिल्डिंग में गर्ल्स पीजी चल रहा था। पड़ोस की इमारत गिरने के बाद इसे खाली कराया गया था। सत्या निकेतन में रविवार को गिरी इमारत में कम से कम 7 लोगों की मौत हुई थी और पांच लोग घायल हुए थे।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इमारत गिरने के मामले में लेबर कॉन्ट्रैक्टर को उत्तर प्रदेश के कासगंज से पकड़ा गया है। यह इस मामले में चौथी गिरफ्तारी है। इससे पहले पीजी के मालिक हरिराम, उनकी पत्नी उर्मिला और बेटे महेश को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। हॉस्टल डेज के पड़ोस में ही बने एक पीजी की कुछ स्टूडेंट्स ने अपने कमरे में आई दरारों का वीडियो बनाया था। दावा किया जा रहा है कि यह बिल्डिंग हॉस्टल डेज के ठीक पहले बना गर्ल्स हॉस्टल ही है। यहां रहने वाली दो छात्राओं ने हॉस्टल डेज में हुए हादसे से कुछ मिनट पहले अपने कमरे की दीवारों और छत की दरारों का वीडियो बनाया था। ये दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी की सेकेंड ईयर की छात्राएं हैं। वीडियो में कहा- लगता है गिरने वाली है।
सोमवार रात तीनों आरोपियों हरिराम बंसल, पत्नी उर्मिला और बेटे महेश को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। जस्टिस भव्य खराल ने हरिराम और उर्मिला को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में, जबकि महेश को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है। पुलिस रिमांड के दौरान इमारत मालिक हरिराम गुप्ता के बेटे महेश गुप्ता ने जांच अधिकारी को बताया कि पीजी संचालित करने वाली कंपनी की शिकायत पर बेसमेंट में पानी भरने और सीलन की समस्या दूर करने के लिए मरम्मत करवाई जा रही थी। बेसमेंट से पानी निकालने के बाद निर्माण कार्य के दौरान पावर ट्रोवेल मशीन भी चलाई जा रही थी। आशंका है कि मशीन से पैदा हुई कंपन और कमजोर हुई संरचना के कारण भवन भरभराकर गिर गया। सत्य निकेतन पीजी हादसा मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने संकेत दिया कि वे इस मुद्दे को केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि देशभर में जर्जर और अवैध इमारतों की स्थिति की समीक्षा करेंगे। अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट पहले भी देशभर में अवैध इमारतों के खिलाफ दिशा-निर्देश जारी कर चुका है और अब उनके पालन की स्थिति की समीक्षा करना चाहता है। अदालत की टिप्पणी को भवन सुरक्षा के मुद्दे पर अहम माना जा रहा है।

मलबे में दबे छात्र ने किया फोन, भेजी लाइव लोकेशन फिर बची जान

-दोस्तों ने सत्य निकेतन पहुंचकर किया रेस्क्यू

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली के सत्य निकेतन में पीजी बिल्डिंग गिरने की घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। इस दर्दनाक हादसे में सात लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए, लेकिन एक घटना ऐसी भी सामने आई है जिसने उम्मीद की किरण जगाई। मलबे के नीचे दबे 19 वर्षीय छात्र नीरज बावा ने अपनी जान बचाने के लिए आखिरी दम तक हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने मलबे के नीचे फंसे रहते हुए पहले अपने दोस्तों को फोन करके मदद मांगी और फिर अपनी लाइव लोकेशन उन्हें भेज दी। यही सूझबूझ उसके लिए अपनी जिंदगी बचाने की सबसे बड़ी उम्मीद बन गई। 19 साल के नीरज बावा पिछले कई दिनों से डीयू छात्रसंघ चुनाव के प्रचार में व्यस्त थे। लगातार 20 दिनों तक चुनाव अभियान में रहने के बाद रविवार को बारिश होने पर वह आखिरकार सत्य निकेतन स्थित अपने हॉस्टल डेज पीजी लौटे थे। जैसे ही वह कमरे में पहुंचे, कुछ ही पल में पूरी इमारत भरभराकर गिर गई और वह मलबे के नीचे दब गए। गनीमत यह रही कि मलबे में फंसे होने के बावजूद नीरज के पास उसका मोबाइल था। उन्होंने तुरंत अपने दोस्तों को फोन किया और कहा, 卐भैया, मुझे बचा लोज मैं यहां मर जाऊंगा।卐 इसके कुछ मिनट बाद उन्होंने अपनी लाइव लोकेशन भी भेज दी ताकि दोस्त सही जगह तक पहुंच सकें। नीरज का दोस्त विष्णु अपने साथियों के साथ तुरंत घटनास्थल पहुंचा।

बाढ़ पीड़ितों के बीच सांसद पप्पू यादव, व्यवस्था पर उठाए सवाल

पूर्णिया, एजेंसी।
निर्दलीय सांसद पप्पू यादव (राजेश रंजन) ने हाल ही में बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों, हाजीपुर और तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर, का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की, खुद खाना बनाया और आर्थिक सहायता भी वितरित की। उन्होंने बिहार सरकार की बाढ़ राहत व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल उठाए। हाजीपुर में मुख्यमंत्री के बाढ़ राहत शिविर का जायजा लेने के दौरान पप्पू यादव ने खाने की गुणवत्ता पर तंज कसा। शिविर में रह रहे लोगों ने शिकायत की कि उन्हें जली हुई दाल, कच्चा चना और चावल दिया जा रहा है, जो खाने लायक नहीं है। लोगों ने यह भी बताया कि नियमित मदद नहीं मिलती और व्यवस्थाएं केवल तब सुधरती हैं जब मुख्यमंत्री या कोई बड़ा अधिकारी दौरा करता है।
पप्पू यादव ने इसे सरकार का दिखावा करार देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के आने पर लाल कारपेट बिछ जाती है, लेकिन उनके जाते ही व्यवस्थाएं धड़ाम हो जाती हैं। उन्होंने हाजीपुर और राघोपुर दोनों जगह लोगों को पांच-पांच सौ रुपये बांटे और महिलाओं को सैनिटरी पैड भी वितरित किए। राघोपुर में पप्पू यादव ने खुद पूरी बनाकर बाढ़ पीड़ितों को खिलाई और वहीं रात्रि विश्राम भी किया, जिससे स्थानीय लोग काफी खुश नजर आए। सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बाढ़ राहत शिविरों में व्यवस्थाएं एकदम लचर हैं। पैसे बांटने के सवाल पर उन्होंने कहा, मैं लंबे समय से लोगों के लिए पैसा बांट रहा हूं। बिहार के लोग मेरे भगवान हैं, दूसरे नेता मंदिर में दूध चढ़ाते हैं, मैं जनता की पूजा करता हूं और जनता को ही चढ़ाता हूं। उन्होंने बाढ़ को लेकर दिए गए बयानों पर भी प्रतिक्रिया दी। ललन सिंह के बयान पर पप्पू यादव ने ऐसे बयान देने वालों की संपत्ति की जांच की मांग की। प्रशांत किशोर के बाढ़ हर साल आता है जैसे सूरज उगता है वाले बयान पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, प्रशांत किशोर नई नवेली दुल्हन हैं, जो सास से सीखकर बयानबाजी कर रहे हैं। सिर्फ राजनीतिक बयान देते हैं, जनता के बीच नजर नहीं आते।

तमिलनाडु में विजय थलपति की सरकार गिराने की तैयारी?

साथ आ रहे सारे विरोधी, बना रहे रणनीति

चेन्नई, एजेंसी।
चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के विरोधी दल उनकी तमिलागा वेत्री कझगम (टीवीके) सरकार के खिलाफ एकजुट होने की तैयारी कर रहे हैं। अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम (एआईएडीएमके) ने प्रमुख विपक्षी दल एमके स्टालिन की डीएमके को साथ आने का सीधा चैलेंज दिया है। एआईएडीएमके ने यह भी कहा है कि टीवीके के खिलाफ अन्य नई पार्टियां भी उनके साथ आ सकती हैं। हालांकि, इस चुनौती पर डीएमके की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
पूर्व मुख्यमंत्री एडापड्डी के. पलनीस्वामी से जब टीवीके के खिलाफ गठबंधन की संभावना के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, हाँ, हम भी टीवीके के खिलाफ हैं। अगर कोई दूसरी पार्टी इसमें शामिल होना चाहती है, तो हम उनका स्वागत करेंगे। हमारा गठबंधन जैसा है, वैसा रहेगा, और अगर दूसरी पार्टियां आना चाहती हैं, तो वे शामिल हो सकती हैं। इस दौरान उन्होंने डीएमके को चुनौती देते हुए कहा, अगर नई पार्टियां हमारे साथ आना चाहती हैं, तो आ सकती हैं। क्या डीएमकेज क्या डीएमके आएगी? क्या आप यह सवाल पूछ सकते हैं? यह राजनीतिक सरगर्मी तब तेज हुई है, जब तमिलनाडु विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद एआईएडीएमके के छह विधायक टूटकर विजय की टीवीके में शामिल हो गए थे, और बचे हुए विधायक भी दो गुटों में बंट गए थे। हालांकि, डीएमके नेता आरएस भारती जून में दोनों दलों के साथ आने से इनकार कर चुके थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर डीएमके और एआईएडीएमके भविष्य में साथ आते हैं, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। वहीं, अगस्त में स्टालिन ने कहा था कि उनकी पार्टी राजनीतिक वापसी करने में सक्षम है और वह पूरे राज्य में मतदाताओं का समर्थन फिर से हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। उन्होंने विजय पर निशाना साधते हुए कहा था, वह (विजय) विधानसभा को फिल्म का सेट समझते हैं और डायलॉग बोलते हैं। इस बीच, टीवीके बुधवार को चेन्नई में सहयोगी दलों के साथ अपनी दूसरी समन्वय बैठक करेगी। हालांकि, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और एमडीएमके के बैठक में शामिल होने की संभावना है। इस बैठक का उद्देश्य गठबंधन को औपचारिक रूप देना, साझा न्यूनतम कार्यक्रम तैयार करना, संचालन समिति गठित करना और गठबंधन का आधिकारिक नाम तय करना है। हालांकि, 2029 के लोकसभा चुनाव में विजय को प्रधानमंत्री पद का संभावित चेहरा बनाए जाने की टीवीके नेताओं की मांग को लेकर कांग्रेस के साथ भी मतभेद सामने आए हैं, क्योंकि कांग्रेस राहुल गांधी को विपक्षी गठबंधन का प्रमुख चेहरा मानती है। टीवीके ने विजय फॉर पीएम की मांग को व्यक्तिगत राय करार दिया है।

झारखंड में लगातार 3 शिक्षा मंत्रियों का निधन , मौत के पीछे के कारणों की हो रही तलाश

रांची (एजेंसी)। झारखंड में शिक्षा मंत्री का पद अब राजनीति में प्रचलित अंधविश्वास की कहानियों में शुमार हो गया है। लगातार तीसरे शिक्षा मंत्री की असामयिक मौत ने इस पद को लेकर गंभीर चर्चा और आशंकाएं पैदा कर दी हैं। पहले जगरनाथ महतो, फिर रामदास सोरेन और अब सुदिव्य सोनू के निधन ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या इस पद के साथ कोई अशुभ जुड़ा है। हेमंत सोरेन ने 2019 में जब भाजपा से सत्ता छीनी, तो उनकी सरकार में 'टाइगर' नाम से मशहूर जगरनाथ महतो को शिक्षा मंत्री बनाया गया था। कोविड महामारी के समय उनके फेफड़े संक्रमित हुए और 6 अप्रैल 2023 को उनका निधन हो गया। जगरनाथ महतो के बाद रामदास सोरेन को शिक्षा मंत्रालय का दायित्व सौंपा गया, लेकिन साल भर में ही वे भी चल बसे। इन दो मौतों के बाद पद पर बैठाने की बारी आई तो तीसरे शिक्षा मंत्री सुदिव्य सोनू को बनाया गया, जो हेमंत सोरेन सरकार के संकटमोचक और जेएमएम में भरोसेमंद नेता माने जाते थे। हाल ही में 6 सितंबर 2026 को उनका भी निधन हो गया, जिसने इस पद के इर्द-गिर्द अंधविश्वास की कहानियों को और बल दे दिया है। यह सिर्फझारखंड की बात नहीं, राजनीति में ऐसे कई अंधविश्वास प्रचलित हैं। बिहार में लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने मंत्री आवास (3, देशरत्न मार्ग) को 'भूतिया' बता दिया था, जब महागठबंधन सरकार गिरने के बाद 2018 में उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा। उनका आरोप था कि भाजपा और नीतीश कुमार ने इस आवास में भूत भेज दिए हैं। पटना में 39, हार्डिंग रोड और स्ट्रैंड रोड का बंगला नंबर 6 जैसे कई अन्य सरकारी आवासों के बारे में भी यही धारणा रही है कि यहां रहने वाले मंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते। उत्तर प्रदेश में भी नोएडा को लेकर राजनीतिकों के बीच ऐसा ही अंधविश्वास रहा कि जो भी मुख्यमंत्री वहां गया, उसकी कुर्सी चली गई। जून 1988 में वीर बहादुर सिंह, 1989 में एन.डी. तिवारी के बाद मुलायम सिंह यादव, मायावती और कल्याण सिंह के उदाहरण दिए जाते थे, जिनकी नोएडा दौरे के बाद सत्ता चली गई। इसी भय से 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहते हुए नोएडा जाने की हिम्मत नहीं जुटा सके।

तिब्बत में तबाही की आहट: 2 घंटे में दो भूकंप, भारत में भी हिली धरती

नई दिल्ली, एजेंसी।
बुधवार की सुबह तिब्बत, नेपाल और भारत में भूकंप का असर दिखाई दिया है। बता दें कि नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (एनसीएस) के अनुसार, आज सुबह ठीक 5 बजकर 33 मिनट पर धरती कांप उठी, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.3 मापी गई और इसका केंद्र जमीन से लगभग 121 किलोमीटर की गहराई में था। इसके करीब दो घंटे बाद, सुबह 7 बजकर 23 मिनट पर एक बार फिर से झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता थोड़ी कम होकर 3.1 दर्ज की गई। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब 3 सितंबर, 2026 को भी तिब्बत क्षेत्र में 5.0 से 5.1 तीव्रता का एक वास्तविक भूकंप दर्ज किया गया था।
तिब्बत में हाल ही में ग्लेशियर टूटने की भयावह घटना के बाद, जहाँ बनी-बनाई इमारतें सेकंड्स में ढह गईं और 1200 से अधिक लोगों की मौत हुई थी, अब धरती

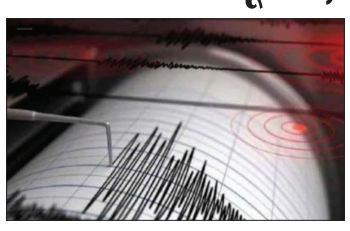

एक बार फिर कांप उठी है। आज सुबह तिब्बत क्षेत्र में दो घंटे के भीतर लगातार दो भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे क्षेत्र में एक नई तबाही की आशंका गहरा गई है। इन झटकों का असर भारत के जम्मू-कश्मीर में भी महसूस किया गया, जहाँ रिक्टर स्केल पर 3.2 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया, जिसका केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। हालांकि इन झटकों की तीव्रता कम थी, फिर भी स्थानीय लोगों में थोड़ी घबराहट फैल गई। तिब्बत के अलावा, नेपाल में भी 5 मैग्नीट्यूड से ऊपर का भूचाल आया, जिससे वहाँ के निवासियों की चिंता बढ़ गई है, खासकर जब वहाँ पहले से ही ग्लेशियर त्रासदी के बाद राहत कार्य चल रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि 3.2 से 4.5 तीव्रता के भूकंप आमतौर पर हल्के माने जाते हैं और इनसे दीवारों में दरारें आने जैसा हल्का नुकसान तो हो सकता है, लेकिन बड़े पैमाने पर तबाही की आशंका बहुत कम होती है। उल्लेखनीय है कि 26 अगस्त 2026 की सुबह तिब्बत और नेपाल की सीमा के पास एक ग्लेशियर टूटा था। इससे आए जोरदार झटके को शुरुआत में 5.2 तीव्रता का भूकंप समझा गया था, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया कि वह भूकंप नहीं बल्कि भारी मात्रा में बर्फ और चट्टानों के गिरने से पैदा हुआ कंपन था। इस आपदा के कारण नेपाल और तिब्बत के सीमाई इलाके में भोटे कोशी-त्रिशुली नदी घाटी में अचानक आई बाढ़ से भारी तबाही मची थी, जिसमें हजारों लोग प्रभावित हुए थे।

दिल्ली हादसे के बाद जम्मू की जर्जर इमारतों पर होने लगे सवाल

-असुरक्षित घोषित परिसर में चल रहे दर्जनों कारोबार, दुकानदार बोले- मजबूरी में काम करना पड़ रहा

जम्मू, एजेंसी।
दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत हादसे के बाद देशभर में असुरक्षित और अवैध निर्माण को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसी कड़ी में जम्मू के वेयरहाउस इलाके में ऐसी इमारतें सामने आई हैं, जिन्हें सरकार औपचारिक रूप से असुरक्षित घोषित कर चुकी है। इसके बावजूद इन इमारतों के ग्राउंड फ्लोर पर व्यापारिक प्रतिष्ठान चल रहे हैं।
शहर के बीच स्थित इन इमारतों में ऊपर की दो मंजिलों पर सरकारी क्वार्टर थे। प्रशासन ने इन्हें असुरक्षित घोषित करने के बाद यहां रह रहे लोगों को क्वार्टर खाली करने के निर्देश दिए। हालांकि, इन्हीं इमारतों के ग्राउंड फ्लोर पर चल रहे दर्जनों व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं। इन दुकानों में कई दर्जन लोग रोजाना काम करते हैं। दुकानदारों और वहां काम करने वाले लोगों का कहना है कि उन्हें इमारत की स्थिति को लेकर डर लगता है, लेकिन वे रोजगार की मजबूरी में काम जारी रखे हुए हैं। उनका कहना है कि सरकार ने सरकारी क्वार्टर तो खाली करा दिए, लेकिन व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की। यदि सरकार दुकानों को भी खाली कराती है और दूसरी जगह उपलब्ध कराती है तो वे वहां जाने के लिए तैयार हैं।
स्थानीय लोगों के मुताबिक, इमारत की जर्जर हालत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आए दिन सीमेंट, सरिया और ईंटों के हिस्से टूटकर नीचे गिरते हैं। आसपास काम करने वाले लोगों ने दावा किया कि कई बार वे इन गिरते मलबों की चपेट में आने से बाल-बाल बचे हैं। उन्होंने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है, ताकि किसी बड़े हादसे से पहले लोगों की जान बचाई जा सके।

शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों को खारिज किया

-पवन खेड़ा से मुलाकात पर दी सफाई

नई दिल्ली, एजेंसी।
शहजाद पूनावाला फिलहाल राजनीति से दूर हैं, लेकिन राजनीति उनसे दूर होती नहीं दिख रही है। हाल ही में सामने आईं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के साथ उनकी तस्वीरों ने अटकलों का नया दौर शुरू कर दिया था। हालांकि, उन्होंने खुद ही सोशल मीडिया पर फोटोज पर सफाई दी है। खास बात है कि पूनावाला पहले ही कांग्रेस में शामिल होने से इनकार कर चुके हैं। वायरल हो रही फोटोज में नजर आ रहा है कि पूनावाला और खेड़ा दोनों साथ खड़े हैं और हाथ मिला रहे हैं। वहीं, पूनावाला ने इस फोटो के पीछे की कहानी सोशल मीडिया पर बताई है। उन्होंने कहा है कि यह तस्वीर एडिट कर शेयर की गई है और एक कार्यक्रम के दौरान ली गई थी। उन्होंने कांग्रेस में जाने से जुड़ी अटकलों पर विराम एक बार फिर लगा दिया है। शहजाद पूनावाला ने लिखा, सभी जग्गा जासूस जैसे लोगों के लिए। मैं कल पायल मेहता के पिता की याद में आयोजित कार्यक्रम में गया था। जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ और कई राजनीतिक दलों के नेता भी वहां पर पहुंचे थे। मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी से भी कई नेता वहां पर आए थे। उन्होंने आगे लिखा, मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त और भाई किरेन रिजिजू से बात कर रहा था और कई पत्रकार उनसे उनकी स्विमिंग की तस्वीरों के बारे में पूछ रहे थे। जैसे ही हमने पवन खेड़ा का जिक्र किया, तो संयोग से वह सामने से चलकर आ रहे थे और मैंने उन्हें अपनी बातों में शामिल कर लिया और राज्यसभा के लिए चुने जाने पर बधाई दी। प्रफुल्ल पटेल जी हमारी बातचीत को सुन रहे थे। उन्होंने आगे लिखा, सभी अफवाहों पर विराम लगाने के लिए, मैं कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहा हूं। मुझे दुनिया की सबसे अच्छी पार्टी भाजपा से कोई दिक्कत नहीं है। और शोक सभाओं में कहीं शामिल होने जैसी बातें नहीं की जाती हैं। कोई भी इतना बेशर्म नहीं है कि ऐसी जगह का इस्तेमाल इन बातों के लिए करे। अगस्त में एक बातचीत में जब कांग्रेस में जाने से जुड़ा सवाल किया गया, तो उन्होंने तंज कस दिया था। पूनावाला ने कहा था, मैं कांग्रेस में शामिल हो जाऊंगा। एक शर्त पर। राहुल गांधी को हटा दो, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा को हटा दो। नेहरू के कामों पर माफी मांगो। उन्होंने साल 2017 में कांग्रेस से दूरी बना ली थी।